

567वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 29 अप्रैल 2022

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल से पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु प्राप्त परियोजनाओं के तकनीकी परीक्षण हेतु राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) की 567वीं बैठक दिनांक 29/04/2022 को डॉ. पी.सी. दुबे की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें समिति के निम्नलिखित सदस्य स्वयं/वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित रहें :—

1. श्री राघवेन्द्र श्रीवास्तव, सदस्य ।
2. प्रो. (डॉ.) रुबीना चौधरी, सदस्य ।
3. डॉ. ए.के. शर्मा, सदस्य ।
4. प्रो. अनिल प्रकाश, सदस्य ।
5. प्रो. (डॉ.) आलोक मित्तल, सदस्य ।
6. डॉ. जय प्रकाश शुक्ला, सदस्य ।
7. डॉ. रवि बिहारी श्रीवास्तव, सदस्य ।
8. श्री ए.ए. मिश्रा, सदस्य सचिव ।

सभी सदस्यों द्वारा अध्यक्ष महोदय के स्वागत के साथ बैठक प्रारंभ करते हुए बैठक के निर्धारित एजेण्डा अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु प्राप्त प्रोजेक्ट्सों का तकनीकी परीक्षण निम्नानुसार किया गया :—

1. Case No 9114/2022 M/s Banafar Granite Industries, Village - Prakash Bamhouri, Tehsil - Gaurihar, Dist. Chhatarpur, MP - 471510, Prior Environment Clearance for Stone Quarry in an area of 1.416 ha. (45,000 cum per annum) (Khasra No. 1901, 1935, 1937, 1938), Village - Prakash Bamhauri, Tehsil - Gaurihar, Dist. Chhatarpur (MP) EIA Consultant: M/s. Aseries Envirotek India Pvt. Ltd. Lucknow U.P.

This is case of Stone Quarry. The application was forwarded by Online SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 1901, 1935, 1937, 1938), Village - Prakash Bamhauri, Tehsil - Gaurihar, Dist. Chhatarpur (MP) 1.416 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

आज दिनांक 29/04/22 को परियोजना प्रस्तावक (ऑनलाईन) और उनकी ओर पर्यावरण सलाहकार श्री अमर सिंह यादव उपस्थित हुए । परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रकरण से संबंधित दस्तावेज जैसे : लीज स्वीकृति पत्र, ग्राम सभा, वन मण्डलाधिकारी की एनओसी, तहसीलदार सर्टिफिकेट, खनिज अधिकारी की 500 मीटर में संचालित खदानों की जानकारी, अनुमोदित खनन योजना, खसरा पंचशाला, फार्म-2, जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, पी.एफ.आर. प्रस्तुत की गई । प्रकरण में परीक्षण में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर (खजिन शाखा) एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 6021 दिनांक 05/10/2021 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में 07 अन्य खदान स्वीकृत/संचालित होने की जानकारी दी गई है, इस प्रकार प्रश्नाधीन खदान को मिलाकर कुल रकबा 18.040 हेक्टेयर होता है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी-1 श्रेणी के अंतर्गत आता है। प्रस्तुतीकरण

567वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 29 अप्रैल 2022

के दौरान अनुमोदित माइन प्लान में उल्लेखित अक्षांश-देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार प्रश्नाधीन खदान के दक्षिण पश्चिम दिशा में 450 मीटर पर कोई संस्थान की बिल्डिंग/रिहायशि मकान दिख रहा है यह क्या है तथा उसकी संरक्षण योजना प्रस्तुत की जानी होगी। प्रकरण के प्रस्तुतीकरण के दौरान यह पाया गया कि लीज क्षेत्र में एक पेड है अतः ट्री इन्वेट्री मय प्रजाति का नाम, ऊचाई एवं गर्थ सहित ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाय। उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेकजर-डी में उल्लेखित मानक शर्तों व विशिष्ट शर्तों के साथ टी.ओ.आर. जारी करने की समिति अनुशंसा करती है :-

1. खदान के दक्षिण पश्चिम दिशा में 450 मीटर पर कोई संस्थान की बिल्डिंग/रिहायशि मकान दिख रहा है यह क्या है तथा उसकी संरक्षण योजना ई.आई.ए. रिपोर्ट में प्रस्तुत की जानी होगी।
2. प्रस्तावित खदान के 2.5 किलोमीटर की परिधि में कार्यरत सभी खदानों व स्टोन केंशरो का क्यूमिलेटिव इंपैक्ट असेसमेंट किया जाये तथा ई.आई.ए. रिपोर्ट में इसका उल्लेख किया जाये।
3. यदि भू-जल का प्रतिछेदन प्रस्तावित हो तो लीज एरिया का हाइड्रो जियोलॉजीकल अध्ययन कर ई.आई.ए. रिपोर्ट में उल्लेख करे।
4. खनन क्षेत्र में 01 पेड है अतः उसकी प्रजाति, ऊचाई एवं गर्थ सहित ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
5. शासकीय भूमि का वर्तमान लैंड यूज क्या है, के संबंध में सक्षम प्राधिकारी का प्रतिवेदन ई. आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें।

2. Case No 9115/2022 Shri Amit Dubey Owner, Village - Chorawar, Tehsil - Basoda, District - Vidisha, MP Prior Environment Clearance for Stone Quarry in an area of 3.0 ha. (7,125 cum per annum) (Khasra No. 47), Village - Chorawar, Tehsil - Basoda, Dist. Vidisha (MP) Env. Consultant M/s. Amaltas Enviro Industrial Consultants LLP, Gurugram

This is case of Stone Quarry. The application was forwarded by Online SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 47), Village - Chorawar, Tehsil - Basoda, Dist. Vidisha (MP) 3.0 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

आज दिनांक 29/04/22 को परियोजना प्रस्तावक (ऑनलाईन) और उनकी ओर पर्यावरण सलाहकार श्री वरुण भारद्वाज उपस्थित हुए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रकरण से संबंधित दस्तावेज जैसे : लीज स्वीकृति पत्र, ग्राम सभा, वन मण्डलाधिकारी की एनओसी, तहसीलदार सर्टिफिकेट, खनिज अधिकारी की 500 मीटर में संचालित खदानों की जानकारी, अनुमोदित खनन योजना, खसरा पंचशाला, फार्म-2, जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, पी.एफ.आर. प्रस्तुत की गई। प्रकरण में

567वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 29 अप्रैल 2022

परीक्षण में पाय गया कि कार्यालय कलेक्टर (खजिन शाखा) एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 5496 दिनांक 03/09/2021 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में 06 अन्य खदान स्वीकृत/संचालित होने की जानकारी दी गई है, इस प्रकार प्रश्नाधीन खदान को मिलाकर कुल रकबा 22.821 हेक्टेयर होता है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी-1 श्रेणी के अंतर्गत आता है। प्रस्तुतीकरण के दौरान अनुमोदित माइन प्लान में उल्लेखित अक्षांश-देशांस के आधार पर गूगल इमेज अनुसार प्रश्नाधीन खदान के पश्चिम दिशा में 490 मीटर पर प्राकृतिक नाला है तथा उत्तर-पश्चिम दिशा में 720 मीटर पर नदी है अतः उसकी संरक्षण योजना प्रस्तुत की जानी होगी। उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेक्जर-डी में उल्लेखित मानक शर्तों व विशिष्ट शर्तों के साथ टी.ओ.आर. जारी करने की समिति अनुशंसा करती है :-

1. प्रश्नाधीन खदान के पश्चिम दिशा में 490 मीटर पर प्राकृतिक नाला है तथा उत्तर-पश्चिम दिशा में 720 मीटर पर नदी है अतः उसकी संरक्षण योजना प्रस्तुत ई.आई.ए. रिपोर्ट में की जानी होगी।
2. प्रस्तावित खदान के 2.5 किलोमीटर की परिधि में कार्यरत सभी खदानों का क्यूमिलेटिव इंपैक्ट असेसमेंट किया जाये तथा ई.आई.ए. रिपोर्ट में इसका उल्लेख किया जाये।
3. यदि भू-जल का प्रतिछेदन प्रस्तावित हो तो लीज एरिया का हाइड्रो जियोलॉजिकल अध्ययन कर ई.आई.ए. रिपोर्ट में उल्लेख करे।
4. शासकीय भूमि का वर्तमान लैंड यूज क्या है, के संबंध में सक्षम प्राधिकारी का प्रतिवेदन ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें।

3. Case No. - 5721/2018 M/s Elite Engineers, 48, Narmada Road, Opposite Johnson Towers, Jabalpur, (M.P.). Prior Environment Clearance for Common Bio Medical Waste Treatment Facility through 200 kg per hour rotary kiln based bio medical incineration project at Village - Kathonda (Madhotal), Distt. - Jabalpur (M.P.) 7(da) Common Biomedical Waste Treatment, Storage and Disposal Facilities (TSDFs). Consultant: M/s Visiontek Consultancy Services Pvt Ltd. Plot No M-22&23, Chandaka Industrial Estate, Patia, Bhubaneswar-751024, Odisha.

This is case of Prior Environment Clearance for expansion in Common Bio Medical Waste Treatment Facility project at Village - Kathonda (Madhotal), Distt. - Jabalpur (M.P.) 7(da) Common Biomedical Waste Treatment, Storage and Disposal Facilities (TSDFs). The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

The case was presented by the PP and their consultant 389th SEAC meeting dated 09.08.2019 wherein PP stated that they have submitted revised form-1, PFR for treatment of 100+100 = 200 KG/hour (fixed hearth based) with Chimney and effluent

**567वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 29 अप्रैल 2022**

treatment plant is proposed and the existing 100 kg/hour kiln will be dismantled. After deliberations committee decided to recommend standard TOR prescribed by the MoEF&CC for conducting the EIA.

PP has applied online for ammendemnt in TOR from 200 kg per hour rotary based bio medical incinerator to 200+100=300 kg per hour static incinerator based bio medical incinerator for expansion as well as modernization in treatment capacities.

The case was scheduled for the presentation today in 567th SEAC meeting dated 29.04.2022 but neither the Project Proponent (PP) nor his representative was present to explain the query which might be raised or to make any commitment which may be desired by the committee during the deliberation. Committee decided to call the PP in subsequent meetings giving last chance and even it the PP remains absent, the case shall be returned to SEIAA assuming that PP is not interested to continue with the project.

4. Case No 9117/2022 Smt. Annu Anjana, Owner, Village Digaonkhurd, Tehsil & Dist. Mandsaur, MP - 458001, Prior Environment Clearance for Murrum and Stone Quarry in an area of 1.520 ha. (Stone - 19589 cum per annum, Murrum - 3918 cum per annum) (Khasra No. 369), Village - Digaonkhurd, Tehsil - Mandsaur, Dist. Mandsaur (MP)

This is case of Murrum and Crusher Stone Quarry. The application was forwarded by Online SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 369), Village - Digaonkhurd, Tehsil - Mandsaur, Dist. Mandsaur (MP) 1.520 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

आज दिनांक 29/04/22 को परियोजना प्रस्तावक और उनकी ओर पर्यावरण सलाहकार उपस्थित हुए । परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रकरण से संबंधित दस्तावेज जैसे : लीज स्वीकृति पत्र, ग्राम सभा, वन मण्डलाधिकारी की एनओसी, तहसीलदार सर्टिफिकेट, खनिज अधिकारी की 500 मीटर में संचालित खदानों की जानकारी, अनुमोदित खनन योजना, खसरा पंचशाला, फार्म-2, जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, पी.एफ.आर. एवं ई.एम.पी. प्रस्तुत की गई। प्रकरण में परीक्षण में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर, (खनिज शाखा) एकल प्रमाण पत्र क्रमांक 2548 दिनांक 07/12/21 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में 01 अन्य खदान स्वीकृत/संचालित है, इस प्रकार प्रश्नाधीन खदान को मिलाकर कुल रकबा 03.093 हेक्टेयर होता है, अतः प्रकरण बी-2 श्रेणी के अंतर्गत आता है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑन लाईन अपलोड माइन प्लॉन के अक्षांश-देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार प्रश्नाधीन खदान स्थल के उत्तर-पश्चिम दिशा में 400 मीटर पर आबादी, पश्चिम दिशा में 140 मीटर पर गौशाला तथा दक्षिण दिशा में 100 मीटर पर रोड़ है । प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने परियोजना प्रस्तावक को सुझाव दिया कि गौशाला में सी.एस.आर. योजना के

567वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 29 अप्रैल 2022

तहत वृक्षारोपण स्थानीय चारा प्रजातियों के साथ किया जाये तथा कम से कम 1.50 मीटर ऊँचाई के पौधे लगाये जाये । प्रस्तुतीकरण पश्चात् निम्नानुसार जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए :-

✓ समिति द्वारा सुझाये अनुसार पुनरीक्षित सी.ई.आर. योजना ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतीकरण के दौरान चाही गई जानकारी दिनांक 29/04/22 द्वारा दी गई, जिसे समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया जो संतोषजनक पाई गई । परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक-ए अनुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता स्टोन— 19,589 मी³ प्रति वर्ष एवं मुरुम 3,918 मी³ प्रति वर्ष ।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 08.83 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 01.96 प्रति वर्ष ।
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 01.25 लाख :-

सी.ई.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि		राशि (रु. में)
1	गौशाला, स्कूल एवं आंगनबाड़ी में 150 वृक्ष ट्री गार्ड एवं नाम प्लेट के साथ प्रजाति – नीम,मौलश्री,कचनार,कदम, पुत्रन्जीवा, सिरिस । गौशाला में पानी हेतु बोर वेल करवाना है ।	75,000
2	डीगाँवखुर्द गाँव के आंगनवाड़ी केंद्र में 1 वर्ष तक पोषण आहार वितरण	50,000
कुल		1,25,000

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 2400 वृक्षों का वृक्षारोपण :

वृक्षारोपण हेतु नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा संख्या
बैरियर जोन	नीम, सिस्सू, करंज,चिरोल, सीताफल, सफ़ेद कस्टार एवं अन्य प्रजातियाँ।	1700
परिवहन मार्ग (पौधों की न्यूनतम ऊँचाई एक मीटर)	नीम,करंज,चिरोल,जंगल जलेबी।	550
गौशाला, विद्यालय में	मौलश्री,पुत्रन्जीवा,कचनार,कदम,नीम,शिरीष एवं अन्य चारा प्रजाति वृक्ष	150
कुल		2400

567वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 29 अप्रैल 2022

5. Case No 9116/2022 M/s Divy Hospitality Pvt. Ltd., Shri Ankesh Goyal, Owner, Plot No. 21, 139, Super Corridor, Dist. Indore, MP - 452010. Prior Environment Clearance for Construction of Proposed New Commercial Building "NRC Business Park" [Total Plot Area = 4500 sqm, Total Proposed Built-up Area = 33079 sqm] at MR-10, Super Corridor, Tehsil & Dist. Indore, (MP). Env. Consultant:- M/s. ENVISOLVE LLP, Indore M.P.

This is case for Prior Environment Clearance for Construction of Proposed New Commercial Building "NRC Business Park" [Total Plot Area = 4500 sqm, Total Proposed Built-up Area = 33,079 sqm] at MR-10, Super Corridor, Tehsil & Dist. Indore, (MP). The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

The case was presented by Env. Consultant Shri Shubham Dubey from M/s. Envisolve LLP, Indore M.P. on behalf of PP, wherein PP submitted the salient features of the project:

S.No.	Information Required	Details
1.	Project Proposal	Proposed New commercial building "NRC Business Park" at MR-10, Super Corridor, Indore.
2.	Total Plot Area	4500 sq.mt.
3.	Total Built up Area	33079sq.mt.
4.	Diesel power generating capacity (power backup)	125 KVA x 1 , 200 KVA x 2
5.	Water requirement	Total water requirement: 95.80 KLD Fresh water requirement: 41.76 KLD Total recycled water generated: 87.45 KLD Flushing Purpose: 54 KLD Green Belt: 6.8 KLD Sewer Line: 22 KLD
6.	Rainwater harvesting details	Recharge pits (existing & proposed): 2 nos Total recharge capacity: 38 m ³ /hr
7.	STP details	Capacity: 100 KLD Type of technology: MBBR
8.	Solid waste generation (kg/day)	Total solid waste: 1122.75 Kg/Day Organic: 674 Kg/Day Non-organic: 337 Kg/Day Inert: 112 Kg/Day E-waste: 354 KG/Annum
9.	Plantation	Trees to be planted: 150 nos Green area: 490.00 m ² % in terms of total plot area: 10.90 %

567वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 29 अप्रैल 2022

10.	Parking	Total parking (ECS): 411 nos Basement: 263 ECS Stilt: 68 nos Open: 80 nos
11.	Remediation cost (If any)	Nil
12.	EMP	Capital: 2.90 Cr Recurring: 1.16 Cr
13.	CER	1,32,00,000 INR
14.	Any other important issue	No

Project Proposal	Proposed New commercial building “NRC Business Park” at MR-10, Super Corridor, Indore.
Total Plot Area	4500 sq.mt.
Total Built up Area	33079 sq.mt.
Location of Project	Plot No. 21, Scheme No. 139, MR-10, Super Corridor, Indore.
Geological Location	Latitude 22°46'43.32"N Longitude 75°51'25.62"E
Building Configuration	BF1 + BF2 + BF3 + Stilt Floor + ground floor + Mezzanine + 1st floor + Service Floor + 2nd floor + 3rd floor + 4th floor + 5th floor + 6th floor + 7th floor + 8th floor + 9th floor + 10th floor.
Altitude of the Site	539 m – 538 m
Estimated Project Cost	INR 66 crores

Salient Features of Project

S.No.	Particulars	Proposed
1.	Net Plot Area	4500 sq.mt.
2.	Built up area	33079 sq.mt.
3.	Ground coverage	Permissible Ground coverage @ 40% = 1800 sq. mt. Proposed Ground coverage @ 40% = 1800 sq. mt.
4.	No. Of Floors	BF1 + BF2 + BF3 + Service floor + ground floor + Mezzanine + 1st floor + Service Floor + 2nd floor + 3rd floor + 4th floor + 5th floor + 6th floor + 7th floor + 8th floor + 9th floor + 10th floor.
5.	Total no. of Offices	296 No.s
6.	Showrooms	11 No.s
7.	Parking Basements	3 No.s
8.	Green cover area	490 sq. mt.

567वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 29 अप्रैल 2022

9.	Parking	Basement parking 1 - 81 ECS Basement parking 2 - 87 ECS Basement parking 3 - 95 ECS Stilt parking – 68 ECS Open parking – 80 ECS.
10.	STP capacity	100 KLD
9.	Total Solid Waste	1122.75 kg/ day
10.	Power Requirement	1626 KW by Madhya Pradesh Paschim Kshetra Vidyut Vitran Company Ltd.
11	DG set details	DG set: 125 KVA of 01 No and 200 KVA of 02 No.
13.	Plot width and depth	Width: 60 m , Depth: 75 m.

The Committee after presentation and deliberation PP was asked to submit following information for further consideration of the project:

- Revised fresh water calculation as suggested by committee considering residential population, commercial activities and floating accordingly STP shall be proposed.
- Revised calculation of ECS nos. at parking considering floating population.
- Submit Hydro-logical study conducted for rain water recharging intake capacity of 02 pits.
- Revised form-I wrt environmental sensitivity.
- Calculation of roof top area where solar power installation are proposed.
- Revised solid waste calculation.
- Details of plantation species with numbers proposed in green belt development with numbers as suggested during presentation.
- Revised CER proposal as suggested by the committee.

PP vide letter dated 29.04.2022 has submitted the revised plantation species details which was placed before the committee. After presentation and submissions made by the PP were found to be satisfactory and acceptable hence the case was recommended for grant of Prior Environment Clearance for Construction of Proposed New Commercial Building "NRC Business Park" [Total Plot Area = 4500 sqm, Total Proposed Built-up Area = 33,079 sqm] at MR-10, Super Corridor, Tehsil & DIst. Indore, (MP). Cat. 8(a) subject to the following special conditions:

Statutory Compliance

- i. The project proponent shall obtain all necessary clearance/permission from all relevant agencies including town planning authority before commencement of work. All the construction shall be done in accordance with the local building byelaws.
- ii. The approval of the Competent Authority shall be obtained for structural safety of building due to earthquakes, adequacy of firefighting equipment etc as per National Building code including protection measures from lightening etc.
- iii. The project proponent shall obtain Consent to Establish/Operate under the provisions of Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981 and the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974 from the concerned State Pollution Control Board/Committee.
- iv. The project proponent shall obtain the necessary permission for drawl of ground water/surface water required for the project from the competent authority.
- v. A certificate of adequacy of available power from the agency supplying power to the project along with the load allowed for the project should be obtained.
- vi. All other statutory clearances such as the approvals for storage of diesel from Chief Controller of Explosives, Fire Department, Civil Aviation Department shall be obtained, as applicable, by project proponents from the respective competent authorities.
- vii. The provisions for the solid Waste (Management) Rules, 2016, e-Waste (Management) Rules, 2016, and the Plastics Waste (Management) Rules, 2016 shall be followed.
- viii. The project proponent shall follow the ECBC/ECBC-R prescribed by Bureau of Energy Efficiency, Ministry of Power Strictly.
- ix. The project area shall be secure through boundary wall and excavated top soil shall not be used in filling of low lying area. The top soil shall be used for greenery development.
- x. The PP shall obtain approval of competent authority for High Rise Building as the proposed height is approx 39.00 meters.

II. Air Quality Monitoring and preservation

- i. Notification GSR 94(E) dated: 25/1/2018 MoEF& CC regarding Mandatory implementation of Dust Mitigation Measures for Construction and Demolition Activities for project requiring Environmental Clearance shall be complied with.
- ii. A management plan shall be drawn up and implemented to contain the current exceedance in ambient air quality at the site.

567वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 29 अप्रैल 2022

- iii. The project proponent shall install system to carryout Ambient Air Quality monitoring for common/criterion parameters relevant to the main pollutants released covering upwind and downwind directions during the construction period.
- iv. 03 Diesel power generating sets 125 KVA x 1, 200 KVA x 2 proposed as source of backup power should be of enclosed type and conform to rules made under the Environment (Protection) Act, 1986. The height of stack of DG sets should be equal to the height needed for the combined capacity of all proposed DG sets. Use of low sulphur diesel. The location of the DG sets may be decided with in consultation with State Pollution Control Board.
- v. Construction site shall be adequately barricaded before the construction begins. Dust, smoke & other air pollution prevention measures shall be provided for the building as well as the site. These measures shall include screens for the building under construction, continuous dust/ wind breaking wills all around the site plastic/tarpaulin sheet covers shall be provided for vehicles bringing in sand, cement, Murram and other construction materials prone to causing dust polluting at the site as well as taking out debris from the site.
- vi. Sand, Murram, loose soil, cement, stored on site shall be covered adequately so as to prevent dust pollution.
- vii. Wet jet shall be provided for grinding and stone cutting.
- viii. Unpaved surface and loose soil shall be adequately sprinkled with water to suppress dust.
- ix. All construction and demolition debris shall be stored at the site (are not dumped on the roads or open spaces outside) before they are properly disposed. All demolition and construction waste shall be managed as per the provisions of the Construction and Demolition Waste Rules, 2016.
- x. The diesel generator sets to be used during construction phase shall be low sulphur diesel type and shall conform to Environmental (Protection) prescribed for air and noise emission standards.
- xi. The gaseous emission from 03 DG sets 125 KVA x 1, 200 KVA x 2 shall be dispersed through adequate stack height as per CPCB standards. Acoustic enclosure shall be provided to the DG sets to mitigate the noise pollution. Low sulphur diesel shall be used. The location of the DG set and exhaust pipe height shall be as per the provisions of the Central Pollution Control Board (CPCB) norms.
- xii. For indoor air quality the ventilation provisions as per National Building Code of India.

III. Water quality monitoring and preservation

- i. The natural drain system should be maintained for ensuring unrestricted flow of water. No construction shall be allowed to obstruct the natural drainage through the site, on wetland and water bodies. Check dams, bio-swales, landscape and other sustainable urban drainage systems (SUDS) are allowed for maintaining the drainage pattern and to harvest rain water.
- ii. Buildings shall be designed to follow the natural topography as much as possible. Minimum cutting and filling should be done.
- iii. The total water requirement during operation phase is 95.80 KLD out of which 41.76 KLD is fresh water requirement and 87.45 KLD will be the total recycled water generated, out of which 54 KLD recycled water will be used for flushing and 6.4 KLD water will be used for horticulture.
- iv. The quantity of fresh water usage, water recycling and rainwater harvesting shall be measured and recorded to monitor the water balance as projected by the project proponent. The record shall be submitted to the Regional Office, MoEF& CC along with six monthly Monitoring reports.
- v. A certificate shall be obtained from the local body supplying water, specifying the total annual water availability with the local authority, the quantity of water already committed the quantity of water allotted to the project under consideration and the balance water available. This should be specified separately for separately for ground water and surface water sources, ensuring that there is no impact on other users.
- vi. At least 20% of the open spaces as required by the local building bye-laws shall be previous. Use of Grass pavers, paver blocks with at least 50% opening, landscape etc. would be considered as previous surface.
- vii. Installation of dual pipe plumbing for supplying fresh water for drinking, cooking and bathing etc and other for supply of recycled water flushing, landscape irrigation, car washing, thermal cooling, conditioning etc. shall be done.
- viii. Use of water saving devices/fixtures (Viz. low flow flushing systems; use of low flow faucets tap aerators etc) for water conservation shall be incorporated in the building plan.
- ix. Separation of grey and black water should be done by the use of dual plumbing system. In case of single stack system separate recirculation lines for flushing by giving dual plumbing system be done.
- x. Water demand during construction should be reduced by use of pre-mixed concrete, curing agents and other best practices referred.

567वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 29 अप्रैल 2022

- xi. The local bye-law construction on rain water harvesting should be followed. If local by-law provision is not available, adequate provisions for storage and recharge should be followed as per the Ministry of Urban Development Model Building bylaws, 2016. Rain water harvesting recharge pits/storage tanks shall be provided for ground water recharging as per the CGWB norms.
- xii. A rain water harvesting plan needs to be designed where the recharge bores of minimum one recharge bore per 5,000 square meter of built up area and storage capacity of minimum one day of total fire water requirement shall be provided. In areas where ground water recharge is not feasible, the rain water should be harvested and stored for reuse. The ground water shall not be withdrawn without approval from the Competent Authority.
- xiii. For rainwater harvesting, 02 recharge pits will be constructed for harvesting rain water. The total recharge capacity of these pits about 38 m³/hr. Mesh will be provided at the roof so that leaves or any other solid waste/debris will be prevented from entering the pit.
- xiv. The RWH will be initially done only from the roof top. Runoff from green and other open areas will be done only after permission from CGWB.
- xv. All recharge should be limited to shallow aquifer.
- xvi. No ground water shall be used during construction phase of the project.
- xvii. Any ground water dewatering should be properly managed and shall conform to the approvals and the guidelines of the CGWA in the matter. Formal approval shall be taken from the CGWA for any ground water abstraction or dewatering.
- xviii. The quality of fresh water usage, water recycling and rainwater harvesting shall be measured and recorded to monitor the water balance as projected by the project proponent. The recorded shall be submitted to the Regional Office, MoEF& CC along with six monthly Monitoring report.
- xix. Sewage shall be treated in the MBBR based STP (Capacity - 100 KLD). The treated effluent from STP shall be recycled/re-used for flushing. AC makes up water and gardening. As proposed, no treated water shall be disposed in to municipal drain.
- xx. The waste water generated from the project shall be treated in STP of 100 KLD capacity (based on MBBR based technology) and then reused for various purposes. No water body or drainage channels are getting affected in the study area because of this project.
- xxi. No sewage or untreated effluent water would be discharged through storm water drains.
- xxii. Periodical monitoring of water quality of treated sewage shall be conducted. Necessary measures should be made to mitigate the odour problems from STP.
- xxiii. Sludge from the onsite sewage treatment including septic tanks, shall be collected, conveyed and disposed as per the Ministry of Urban Development, Control Public

Health and Environmental Engineering Organization (CPHEEO) Manual on Sewerage and Sewage Treatment Systems, 2013.

IV. Noise monitoring and prevention

- i. Ambient noise levels shall conform to residential area/commercial area/industrial area/silence zone both during day and night as per Noise Pollution (Control and Regulation) Rules, 2000. Incremental pollution loads on the ambient air and noise quality shall be closely monitoring during construction phase. Adequate measures shall be made to reduce ambient air and noise level during construction phase, so as to conform to the stipulated standards by CPCB/SPCB.
- ii. Noise level survey shall be carried as per the prescribed guidelines and report in this regard shall be submitted to Regional Officer of the Ministry as a part of six-monthly compliance report.
- iii. Acoustic enclosures for DG sets, noise barriers for ground run bays, ear plugs for operating personnel shall be implemented as mitigation measures for noise impact due to ground sources.

V. Energy Conservation measures.

- i. Compliance with the Energy Conservation Building Code (ECBC) of Bureau of Energy Efficiency shall be ensured, Building in the State which have notified their own ECBC, shall comply with the State ECBC.
- ii. Outdoor and common area lighting shall be LED.
- iii. Concept of passive solar design that minimize energy consumption in buildings by using design elements, such as building orientation, landscaping, efficient building envelope, appropriate fenestration, increased day lighting design and thermal mass etc. shall be incorporated in the building design. Wall, window, and roof u-values shall be as per ECBC specifications.
- iv. Energy Conservation measures like installation of CFLs/LED's for the lighting the area outside the building should be integral part of the project design and should be in place before project commissioning.
- v. Solar, wind or other renewable energy shall be installed to meet electricity generation equivalent to 1% of the demand load or as per the state level /local building bye-laws requirement, which is higher.
- vi. Solar power shall be used for lighting in the apartment to reduce the power load on grid. Separate electric meter shall be installed for solar power. Solar water heating shall be provided to meet 20% of the hot water demand of the commercial and institutional building or as per the requirement of the local building bye-laws,

567वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 29 अप्रैल 2022

whichever is higher. Residential buildings are also recommended to meet its hot water demand from solar water heaters, as far as possible.

VI. Waste Management

- i. Total waste 1122 Kg/day, this consist all types of wastes (as Organic waste 674 Kg/day and non- organic waste 337 Kg/day), Inert waste 112 Kg/day, E- waste 354 Kg/Annum, and these all type of waste shall be treated/ disposed off as per provision made in the MSW Rules 2016.
- ii. A certificate from the competent authority handling municipal solid wastes, indicating the existing civic capacities of handling and their adequacy to cater to the MSW generated from project shall be obtained.
- iii. Disposal of muck during construction phase shall not create any adverse effect on the neighboring communities and be disposed taking the necessary precautions for general safety and health aspects of people, only in approved sites with the approval of competent authority.
- iv. Separate wet and dry bins must be provided in each unit and at the ground level for facilitating segregation of waste. Solid waste (0.4 ton/day) shall be segregated into wet garbage and inert materials.
- v. All non-biodegradable waste shall be handed over the authorized recyclers for which a written lie up must be done with the authorized recyclers.
- vi. Any hazardous waste generated during construction phase, shall be disposed off as per applicable rules and norms with necessary approvals of the State Pollution Control Board.
- vii. Use of environment friendly materials in bricks, blocks and other construction materials, shall be required for at least 20% of the construction materials quantity. These include fly ash brick, hollow bricks, AACs, Fly Ash Lime Gypsum block, compressed earth blocks and other environmental friendly materials.
- viii. Fly ash should be used as building material in the construction as per the provisions of Fly Ash Notification of September, 1999 and amended as on 27th August, 2003 and 25th January, 2016 Ready mixed concrete must be used in building construction.
- ix. Any wastes from construction and demolition activities related thereto shall be managed so as to strictly conform to the construction and Demolition Rules, 2016.
- x. Used CFLs and TFLs should be properly collected and disposed off/sent for recycling as per the prevailing guidelines/rules of the regulatory authority to avoid mercury contamination.

VII. Green Cover

- i. Total 150 trees shall be planted in the area of 490.00 m² (10.09 % of total plot area) within the project site.
- ii. Where the trees need to be cut with prior permission from the concerned local Authority, Compensatory plantation in the ratio of 1:10 (i.e. planting of 10 trees for every 1 tree that is cut) shall be done and maintained. Plantations to be ensured species (cut) to species (planted). Area for green belt development shall be provided as per the details provided in the project document.
- iii. Topsoil should be stripped to depth of 20 cm from the areas proposed for buildings, roads, paved areas, and external services. It should be stack plied appropriately in designated areas and reapplied during plantation of the proposed vegetations on site.

VIII Transport

- i. A comprehensive mobility plan, as per MoUD best practices guidelines (URDPFI), shall be prepared to include motorized, non-motorized, public and private network. Road should be designed with due consideration for environment and safety of users. The road system can be designed with these basic criteria.
 - a. Hierarchy of roads with proper segregation of vehicular and pedestrian traffic
 - b. Traffic calming measures.
 - c. Proper design of entry and exit points
 - d. Parking norms as per local regulation
- ii. Vehicles hired for bringing construction material to the site should be in good condition and should have a pollution check certificate and should conform to applicable air and noise emission standards be operated only during non-peak hours.
- iii. Total proposed Parking's arrangement for 411 ECS (Stilt parking 68 ECS, Basement 263 ECS and 80 ECS for open parking).
- iv. A detailed traffic management and traffic decongesting plan shall be drawn up to ensure that the current level of service of the road within a 05 Kms radius of the project as maintained and improved upon after the implementation of the project. This plan should be based on cumulative impact of the development and increased habitation being carried out or proposed to be carried out by the project or other agencies in this 05 Kms radius of the site in different scenarios of space and time and the traffic management and the PWD/competent authority for road augmentation and shall also have their consent to the implementation of components of the plan which involve the participation of these departments.

IX. Human health issues

- i. All workers working at the construction site and involved in loading, unloading, carriage of construction material and construction debris or working in any area with dust pollution shall be provided with dust mask.
- ii. For indoor air quality the ventilation provisions as per National Building Code of India.
- iii. Emergency preparedness plan based on the Hazard identification and Risk Assessment (HIRA) and Disaster Management Plan shall be implementation.
- iv. Provision shall be made for the housing of construction labour within the site with all necessary infrastructure and facilities such as fuel for cooking, mobile toilets, mobile, STP, safe drinking water, medical health care, crèche etc. The housing may be in the form of temporary structures to be removed after the completion of the project.
- v. Occupational health surveillance of the workers shall be done on a regular basis.
- vi. A First Aid Room shall be provided in the project both during construction and operations of the project.

X. EMP & Corporation Environment Responsibility

- i. The project proponent shall comply with the provisions contained in this Ministry's OM vide F.No. 22-65/2017-IA.III dated: 1st May 2018, as applicable, regarding Corporate Environment Responsibility.
- ii. The company shall have a well laid down environmental policy duly approved by the Board of Directors. The Environmental policy should prescribe for standard operating procedures to have proper checks and balance and to bring into focus any infringements/deviation/violation of the environmental/forest/wildlife norms/conditions. The company shall have defined system of reporting infringements/deviation/violation of the Environmental/forest/wildlife norms/conditions and/or shareholders/stake holders. The copy of the board resolution in this regard shall be submitted to the MoEF&CC as a part of six monthly reports.
- iii. A separate Environmental Cell both at the project and company head quarter with qualified personnel shall be set up under the control of senior Executive, who will directly to the head of the organization.
- iv. Action plan for implementing EMP and environmental conditions along with responsibility matrix of the company shall be prepared and shall be duly approved

567वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 29 अप्रैल 2022

by competent authority. The year wise funds earmarked for environmental protection measures shall be kept in separate account and not to be diverted for any other purpose. Year wise progress of implementation of action plan shall be reported to the Ministry/Regional Office along with the Six Monthly Compliance Report.

- v. For Environment Management Plan PP has proposed Rs. 290.0 Lacs as capital and Rs. 116.0 Lacs as recurring cost for this project.
- vi. PP has proposed Rs 132.00 Lacs towards the development of Bio-diversity garden, medicinal plants and other activities as suggestwd by Registrar of Dr. B.R. Ambedkar University through forest department at Dr. B.R. Ambedkar University of Social Sciences University (BRAUSS) near Ambedkar Nagar, Madhya Pradesh as per approved landuse plan for green area development of university through Registrar (minimum plants should be 3000 nos.) which shall commence from Ist Year i.e. onset of mansoon season of 2022, under Corporate Environment Responsibility (CER) and a copy of this proposal shall be submitted to the Registrar, Dr. B.R. Ambedkar University, Ambedkar Nagar, Madhya Pradesh.

XI. Miscellaneous

- i. The project authorities must strictly adhere to the stipulation made by the MP Pollution Control Board and the State Government.
- ii. The project proponent shall abide by all the commitments and recommendations made in the EIA/EMP report, commitment made during Public Hearing and also that during their presentation to the State Expert Appraisal Committee (SEAC)
- iii. No further expansion or modification in the plant shall be carried out without prior approval of the Ministry of Environment, Forests and Climate Change (MoEF&CC).
- iv. Concealing factual data or submission of false/fabricated data may result in revocation of this environmental clearance and attract action under the provisions of Environment (Protection) Act, 1986.
- v. The above conditions shall be enforced, inter-alia under the provisions of the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974, the Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981, the Environment (Protection) Act, 1986, Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016 and the Public Liability Insurance Act, 1991 along with their amendments and Rules and any other orders passed by the Hon'ble Supreme Court of India/High Courts and any other Court of Law relating to the subject matter.

**567वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 29 अप्रैल 2022**

6. Case No 6881/2020 Shri Shivmangal Singh Gour, Basant Vihar, 301, Gulmohar Basant Vihar, Dist. Indore, MP Prior Environment Clearance for Stone Quarry in an area of 3.00 ha. (10,000 cum per annum) (Khasra No. 860/1/KA/1), Village - Chormari, Tehsil - Rampur Baghelan, Dist. Satna (MP). EIA Consultant: M/s. Aseries Envirotek India Pvt. Ltd. Lucknow U.P.

This is case of Stone Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site at (Khasra No. 860/1/KA/1), Village - Chormari, Tehsil - Rampur Baghelan, Dist. Satna (MP) 3.00 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) की बैठक क्रमांक 429वीं दिनांक 16/03/2020 में टॉर (TOR) की अनुशंसा की गई थी ।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल द्वारा परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ई.आई.ए. रिपोर्ट राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) को ऑन लाईन प्रेषित की गई है ।

आज दिनांक 29/04/22 को परियोजना प्रस्तावक ऑन-लाईन और उनकी ओर पर्यावरण सलाहकार श्री अमर सिंह यादव उपस्थित हुए । प्रस्तुतीकरण के दौरान यह पाया गया कि खदान के दक्षिण दिशा में 65 मीटर पर नाला है तथा खदान क्षेत्र में 02-03 पेड़ हैं जिसे नहीं काटा जावेगा । प्रकरण के परीक्षण में पाया गया कि एकल प्रमाण पत्र के अनुसार खदान की वन क्षेत्र से दूरी 75 मीटर है । संभागायुक्त की अध्यक्षता में सम्पन्न बैठक कार्यवाही विवरण दिनांक 08/05/2018 अनुसार वन मण्डलाधिकारी, वन मण्डल, सतना के प्रतिवेदन अनुसार आवेदित स्थल से 75 मीटर की दूरी पर स्थित है । वन सीमा की ओर चैनलिंग, फेनसिंग का कार्य संपादित कराने की शर्त के आधार पर प्रकरण का निराकरण किये जाने का निर्णय लिया गया । परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि इस खदान की जनसुनवाई के दौरान वृक्षारोपण, परिवहन मार्गों का रख-रखाव, श्रमिकों हेतु डस्ट मास्क एवं सामाजिक कल्याण के कार्य (जैसे स्कूल की मरम्मत, खेल सामग्री, शौचालय का निर्माण, पेय जल की व्यवस्था एवं रोड़ के दोनों ओर वृक्षारोपण) किये जाने हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुए थे, जिनको उनके द्वारा सी.ई.आर. में शामिल किया गया है । परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि खनन हेतु कंट्रोल ब्लास्टिंग की जावेगी तथा खनिज परिवहन के दौरान लगातार सड़क पर जल छिड़काव किया जायेगा । प्रस्तुतीकरण के पश्चात् परियोजना प्रस्तावक को निम्नानुसार जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए :-

✓ समिति द्वारा सुझाये अनुसार पुनरीक्षित सी.ई.आर. योजना ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतीकरण के दौरान चाही गई जानकारी दिनांक 29/04/22 द्वारा दी गई, जिसे समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई, जो संतोषजनक पाई गई । परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से

567वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 29 अप्रैल 2022

समिति द्वारा विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक-ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता स्टोन –10,000 मी³ प्रति वर्ष वर्ष ।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 16.31 लाख एवं रिकरिंग 03.97 लाख प्रति वर्ष ।
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 0.90 लाख :-

1.	सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधि	राशि (रु. में)
	स्थानीय ग्रामीणों के लिए वर्ष में 03 बार नियमित स्वास्थ्य शिविर की व्यवस्था की जायेगी ।	20,000/-
2.	200 नग मास्क और 04 दस लीटर की सैनीटाइजर की बोतल चोरमरी गाँव में बटवायी जायेगी ।	5,000/-
3.	चोरमरी प्राथमिक विद्यालय के दीवाल व शौचालय की मरम्मत करायी जायेगी ।	30,000/-
4.	प्राथमिक विद्यालय चोरमरी में एक नलकूप का निर्माण व 02 नग खेल के सामान व बैण्डमिटन, फुटबाल, वालीबाल, का वितरण किया जायेगा ।	35,000/-
कुल		90,000/-

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 3600 वृक्षों का वृक्षारोपण :

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन व नॉन माईनिंग एरिया	शीशम, नीम, बरगद, खमेर, चरौल, अंजन, सेन्सीबनीया, सीताफल एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ ।	1700
2.	ग्राम चोरमरी परिवहन मार्ग (पौधों की न्यूनतम ऊँचाई एक मीटर)	नीम, पीपल, सेमल एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ,	1500
3	ग्रामपंचायत चोरमरी के ग्रामवासियों को वितरण हेतु	बेल, इमली, आवंला, आम, अमरुद, कटहल, एवं अन्य स्थानीय फलदार प्रजातियाँ ।	390
4.	शासकीय चोरमरी विद्यालय	कदंब, अमलतास अशोक नीम गुलमोहर	10
कुल			3600

567वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 29 अप्रैल 2022

7. Case No 7164/2020 Shri Dadai Singh Gond, Village - Sardaman, Tehsil - Hanumana, Dist. Rewa, MP Prior Environment Clearance for Stone Quarry in an area of 4.50 ha. (97,470 cum per annum) (Khasra No. 10/1/ka/1, 10/1/ka/2, 10/1/ka/3, 10/1/ka/4, 10/1/ka/5, 13/1, 13/2, 13/3, 13/4, 13/5), Village - Sardaman, Tehsil - Hanumana, Dist. Rewa (MP). EIA Consultant: M/s. In Situ Enviro Care, Bhopal.

This is case of Stone Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site at (Khasra No. 10/1/ka/1, 10/1/ka/2, 10/1/ka/3, 10/1/ka/4, 10/1/ka/5, 13/1, 13/2, 13/3, 13/4, 13/5), Village - Sardaman, Tehsil - Hanumana, Dist. Rewa (MP) 4.50 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

PP has submitted a copy of approved Mining Plan, DSR report, information in the lease's within 500 meters radius around the site and other requisite information in the prescribed format duly verified in the Collector Office letter no. 1114 dated: 11/5/2020 has reported that there are 02 more mines operating or proposed within 500 meters around the said mine with total area of 12.243 ha including this mine.

Earlier this case was scheduled for presentation and discussion in 442nd SEAC dated 16/06/2020 wherein ToR was recommended.

PP has submitted the EIA report vide letter dated 29/6/21 which was forwarded through SEIAA vide letter no. 1352 dated 05/07/21 and the same was scheduled in the agenda.

PP and their consultant presented the EIA before the committee in 503rd meeting dated 22/7/2021 . During presentation, PP submitted that there are 02 more mines operating or proposed within 500 meters radius around this mine with total area of 12.243 ha. Hence, EIA and public hearing is conducted after obtaining TOR. It was further observed that as per Google image based on coordinates provided by PP that a Kachcha road is in existence at a distance of approximately 55 meters from lease towards south side. Moreover 04-06 houses/hutments are in existence with some trees within lease for which PP submitted that these are temporary huts/ shelters. In the DFO, letter vide no 338 dated 10/01/2020 forest area is at a distance of approx. 42.45 meters from the lease boundary, for which PP has obtained approval from Divisional Commissioner Level Forest Committee meeting held on 20.02.2020 wherein conditional permission was given as 100 meter is to be left from the forest area to lease. After presentation

567वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 29 अप्रैल 2022

committee asked PP to submit response on following issues including irrelevant/misleading information provided in From-II, such as:

1. Revised surface plan leaving 100 m area w.r.t. nearby forest area as according to Divisional Commissioner Level Forest Committee meeting held on 20.02.2020.
2. R&R plan w.r.t. to 04-06 kachcha house/hutments within lease area.
3. Distance of houses in existence around the mines and their protection plan in line with the guidelines stipulated by CPCB.
4. In point no.14.6- Ground water table is shown as 1.60m to 17.70m which needs justification as proposed depth is 40 meters (see point 35-11).
5. In point no.15- in place of permission for GW withdrawal, lease sanction letter is attached.
6. In point no. 16- When manpower (permanent/temporary) is proposed in point no. 31, then how the waste water volume will be “Zero”.
7. In point no. 17- provide relevant information for solid waste generation/management. How top soil can be backfilled?
8. In point no. 19- No power supply, please justify the statement.
9. In point no. 32- why detailed green belt plan is not attached.
10. In point no. 35 (10)- No top soil, please justify as it is appear from the google image that lease has top soil.
11. Properly address following issues raised during public hearing with plan/proposal:
 - Issue of Fly rocks at local residents houses.
 - Dust problem.
 - Crop damage.
 - Cracks in the houses due to blasting.
 - Tree plantation at public places and in school premises with adequate protection measures.
 - Fruit bearing tree saplings (such as Jackfruit, Custard apple, Mango, Guava, Munga, Orange etc) distribution in adjoining villages
12. Proposal of boundary wall through OB.
13. Proposal for plantation in adjoining forest land through concerned DFO forest and commitment that commensurate budget will be transferred to for plantation to DFO.
14. Proposal for providing solar cookers / LPG gas cylinders under “Ujjwala Yojna” to mine workers under CER.

567वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 29 अप्रैल 2022

15. Commitment that mineral evacuation road/transportation road shall be made pucca and commensurate budgetary allocations shall be proposed in the EMP.
16. Commitment that plantation shall be carried out through Govt. agency (such as Van Vikas Nigam/Van Samiti under monitoring and guidance of Range officer / Gram Panchayat / Forest Department / Agricultural department by transferring proportionate funds to them.
17. Commitment that local palatable perennial grass species proposed for grassland development/fodder development shall be added in the species for grassland/fodder development and this activity shall be taken up through Local DFO on degraded land suitable for the purpose or through Gram Panchayat on suitable community land.
18. Commitment that dense plantation/ Wood Lot shall be developed (preferably using “Miyawaki Technique”) in 7.5m barrier zone left for plantation with the concern CCF (R&E Circle Bhopal).
19. PP’s commitment that activities proposed in the CER and plantation scheme will be completed within initial 03 years of the project and in the remaining years shall be maintained.
20. Proposal for CER activates should be based upon Gram Panchayat Annual Action Plan and commitment made during public hearing.

PP vide their letter dated 09/08/2021 submitted query reply hard copy as well as on “Parivesh Portal”. The query reply was presented by Consultant & RQP Shri Ajay Mohan, authorized by PP.

PP and their consultant presented the query before the committee in 509th meeting dated 24/8/21. During presentation it was observed by committee that comments / feedback given by local peoples during public hearing were very critical considering environmental issues such as issue of fly rocks at local resident’s houses, dust problem, crop damage and cracks in the houses due to blasting. Committee further observed through Google image that two houses are in existence on the southern side of lease. PP submitted that this is a proposal for new mine and they have yet not started mining and have left non mining area from the western and eastern side of lease considering habitations as per CPCB guidelines. It was further submitted by him that persons who have taken objections in public hearing are not residing in near vicinity of the proposed mining lease and raised the issues due to rivalry. The houses which are in existence within the lease belong to lease owner and will be dismantled during mining and competent authority has sanctioned the lease considering all these aspects as per MMR, 1996 and Tehsildar has also mentioned in his certificate issued on dated 10/01/20 that the lease is away from the village and school.

**567वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 29 अप्रैल 2022**

After deliberations committee asked PP to submit credible proof regarding status of two houses located (approx. 25 meters away) on the southern side of the lease, comprehensive mitigation plan and mark resident's house location on map who have taken objection during public hearing.

परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति की 509वीं बैठक दिनांक 24/8/21 में चाही गई जानकारी उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण प्रकरण को समिति की 534वीं बैठक दिनांक 15/12/21 में नस्तीबद्ध (Delist) करने की अनुशंसा सहित सिया को अग्रिम कार्यवाही हेतु भेजा गया था, जिसे मान्य करते हुए सिया 698वीं बैठक दिनांक 28/12/21 को प्रकरण को डिलिस्ट कर दिया गया था ।

परियोजना प्रस्तावक ने पत्र दिनांक 16/3/22 के द्वारा प्रकरण को रिलिस्ट करने का अनुरोध किया गया, जिसे मान्य करते हुए सिया की 718वीं बैठक दिनांक 12/04/22 को प्रकरण को रिलिस्ट कर सेक को परीक्षण हेतु प्रेषित किया गया है ।

आज दिनांक 29/4/22 को प्रकरण को समिति के समक्ष विचार हेतु रखा गया । प्रकरण के परीक्षण में पाया गया कि रिलिस्ट करने बावत् परियोजना प्रस्तावक ने ऑनलाईन आवेदन पत्र दिनांक 16/3/22 प्रस्तुत किया है । प्रकरण आज चर्चा हेतु निर्धारित था समिति ने नस्ती के अवलोकन से पाया कि परियोजना प्रस्ताव ने पत्र दिनांक 16/3/22 के द्वारा प्रस्तुत रिलिस्ट अनुरोध के साथ समिति की 509वीं बैठक दिनांक 24/8/21 में चाही गई जानकारी प्रस्तुत नहीं की है । परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति की 509वीं बैठक दिनांक 24/8/21 में चाही गई जानकारी उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण तथा प्रकरण के लम्बे समय तक लम्बित रहने के कारण ही समिति की 534वीं बैठक दिनांक 15/12/21 में नस्तीबद्ध (Delist) करने की अनुशंसा सहित सिया को अग्रिम कार्यवाही हेतु भेजा गया था ।

अतः समिति की अनुशंसा है कि जब तक परियोजना प्रस्तावक सेक/सिया द्वारा वांछित जानकारी रिलिस्ट हेतु प्रस्तुत आवेदन के साथ संलग्न न करें तब तक ऐसे प्रकरणों को रिलिस्ट न किया जाये अन्यथा लम्बित प्रकरणों के संख्या में वृद्धि होगी । चूँकि इस प्रकरण में भी परियोजना प्रस्तावक ने सेक की 509वीं बैठक दिनांक 24/8/21 में चाही गई जानकारी रिलिस्टिंग अनुरोध के साथ प्रस्तुत नहीं की है, अतः समिति पुनः इस प्रकरण को नस्तीबद्ध करने की अनुशंसा करते हुए प्रकरण आगामी कार्यवाही हेतु सिया को भेजने का निर्णय लेती है ।

8. Case No 9119/2022 Shri Jitendra Shroti, Owner, D-24, Vivek Vihar Colony, Lashkar Grid, Dist. Gwalior, MP - 474001 Prior Environment Clearance for Stone Quarry in an area of 2.591 ha. (50,009 cum per annum) (Khasra No. 1974/2/Min-1, 2082), Village - Daurar, Tehsil - Ghatigaon, Dist. Gwalior (MP)

This is case of Stone Quarry. The application was forwarded by Online SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 1974/2/Min-1, 2082), Village - Daurar,

567वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 29 अप्रैल 2022

Tehsil - Ghatigaon, Dist. Gwalior (MP) 2.591 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

प्रकरण आज दिनांक 29/04/22 को प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध था किंतु परियोजना प्रस्तावक एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार ऑन लाईन/ऑफ लाईन प्रस्तुतीकरण हेतु समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुए हैं। अतः समिति ने निर्णय लिया कि परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तुतीकरण हेतु अंतिम अवसर देते हुए प्रकरण आगामी बैठक में रखा जाये तथा यदि फिर भी परियोजना प्रस्तावक अनुपस्थित रहते हैं तो इस प्रकरण निरस्त (डिलिस्ट) करते एसईआईए को अग्रिम कार्यवाही हेतु भेजा जावे।

9. Case No 9120/2022 Shri Amit Singh, Owner, Village Bhati Jungle, Tehsil Mauganj, Dist. Rewa MP - 486771 Prior Environment Clearance for Stone Quarry in an area of 2.0 ha. (37,102 cum per annum) (Khasra No. 145/1), Village Bhati Jungle, Tehsil - Mauganj, Dist. Rewa (MP)

This is case of Stone Quarry. The application was forwarded by Online SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 145/1), Village - Bhati Jungle, Tehsil - Mauganj, Dist. Rewa (MP) 2.0 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

आज दिनांक 29/04/22 को परियोजना प्रस्तावक और उनकी ओर पर्यावरण सलाहकार उपस्थित हुए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रकरण से संबंधित दस्तावेज जैसे : लीज स्वीकृति पत्र, ग्राम सभा, वन मण्डलाधिकारी की एनओसी, तहसीलदार सर्टिफिकेट, खनिज अधिकारी की 500 मीटर में संचालित खदानों की जानकारी, अनुमोदित खनन योजना, खसरा पंचशाला, फार्म-2, जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, पी.एफ.आर.एवं ई.एम.पी. प्रस्तुत की गई। प्रकरण में परीक्षण में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर, (खजिन शाखा) एकल प्रमाण पत्र क्रमांक 5967 दिनांक 12/10/21 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में 01 अन्य खदान स्वीकृत/संचालित है, इस प्रकार प्रश्नाधीन खदान को मिलाकर कुल रकबा 04.00 हेक्टेयर होता है, अतः प्रकरण बी-2 श्रेणी के अंतर्गत आता है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑन लाईन अपलोड माइन प्लॉन के अक्षांश-देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार प्रश्नाधीन खदान स्थल के उत्तर दिशा में 500 मीटर पर जलाशय है। इसी प्रकार पश्चिम दिशा में 20 मीटर पर मौसमी नाला है, अतः वहाँ से 30 मीटर का सेट-बैक छोड़ना होगा। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि खदान क्षेत्र में 01 पेड़ है जिसे नहीं काटा जावेगा। प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक से निम्नानुसार जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए :-

- ✓ समिति द्वारा सुझाये अनुसार पुनरीक्षित सी.ई.आर. योजना।
- ✓ पश्चिम दिशा में 20 मीटर पर मौसमी नाला है, अतः वहाँ से 30 मीटर का सेट-बैक दिखाते हुए पुनरीक्षित सरफेस मैप।
- ✓ समिति द्वारा सुझाये अनुसार पुनरीक्षित वृक्षारोपण योजना।

567वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 29 अप्रैल 2022

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतीकरण के दौरान चाही गई जानकारी दिनांक 29/04/22 द्वारा दी गई, जिसे समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया जो संतोषजनक पाई गई। परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक-ए अनुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता स्टोन— 37,102 मी³ प्रति वर्ष।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में कैपिटल राशि रु. 13.83 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 04.37 प्रति वर्ष।
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 0.50 लाख :-

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधि	राशि रु. में
<ul style="list-style-type: none"> ग्राम भाटी जंगल के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में 1 स्टेचर एवं 2 व्हील चेयर्स उपलब्ध कराई जाएगी। निर्माणाधीन गौ शाला में पानी की टंकी (3500 लीटर – 2 मीटर X 0.4064 मीटर) रखवा कर टैंकर द्वारा पानी की उचित सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। 	15,000/-
	35,000/-
योग	50,000/-

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 2400 वृक्षों का वृक्षारोपण :

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन में	चिरोल, नीम, सीताफल, जंगल जलेबी, सिस्सू, पीपल, सफेद कस्टार, करंज एवं अन्य स्थानीय प्रजातिया	900
2	परिवहन मार्ग में (पौधों की न्यूनतम ऊँचाई एक मीटर)	पीपल, करंज, सप्तपर्णी, चिरोल, जंगल जलेबी, पुत्रंजीवा, नीम, सिस्सू एवं अन्य स्थानीय प्रजातिया ट्री-गार्ड के साथ।	500
3	ग्राम भाटी जंगल के नजदीक स्थित प्राथमिक उपचार केंद्र में	पुत्रंजीवा, मोलश्री, संतरा, पीपल, आम, इमली, मुनगा, कटहल करंज एवं अन्य स्थानीय प्रजातिया	50
4.	ग्राम भाटी जंगल के गौ शाला परिसर में उपलब्ध क्षेत्र पर	पुत्रंजीवा, मोलश्री, करंज, पीपल, सप्तपर्णी, चिरोल, करंज, सिरिस, कचनार एवं अन्य स्थानीय चारा प्रजातियाँ।	200

567वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 29 अप्रैल 2022

5.	ग्रामीणों में पौधों का वितरण	आम, जामुन, अमरुद, आँवला, अनार, इमली, निम्बू, कटहल एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	750
कुल			2400

10. Case No 9121/2022 Shri Arjun Singh Kheechi, Owner, Pachore Road, Shujalpur City, Tehsil Shujalpur, Dist. Shajapur, MP - 465333 Prior Environment Clearance for Stone Quarry in an area of 2.0 ha. (4,763 cum per annum) (Khasra No. 3/1, 3/2, 18/1, 18/3), Village - Shyampur Chitauni, Tehsil - Shujalpur, Dist. Shajapur (MP)

This is case of Stone Quarry. The application was forwarded by Online SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 3/1, 3/2, 18/1, 18/3), Village - Shyampur Chitauni, Tehsil - Shujalpur, Dist. Shajapur (MP) 2.0 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

आज दिनांक 29/04/22 को परियोजना प्रस्तावक और उनकी ओर पर्यावरण सलाहकार उपस्थित हुए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रकरण से संबंधित दस्तावेज जैसे : लीज स्वीकृति पत्र, ग्राम सभा, वन मण्डलाधिकारी की एनओसी, तहसीलदार सर्टिफिकेट, खनिज अधिकारी की 500 मीटर में संचालित खदानों की जानकारी, अनुमोदित खनन योजना, खसरा पंचशाला, फार्म-2, जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, पी.एफ.आर.एवं ई.एम.पी. प्रस्तुत की गई। प्रकरण में परीक्षण में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर, (खनिज शाखा) एकल प्रमाण पत्र क्रमांक 1122 दिनांक 17/09/21 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदान स्वीकृत/संचालित नहीं है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी-2 श्रेणी के अंतर्गत आता है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑन लाईन अपलोड माइन प्लॉन के अक्षांश-देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार प्रश्नाधीन खदान स्थल के उत्तर-पश्चिम दिशा में 370 मीटर पर एक जल रोकने की संरचना, उत्तर दिशा में 220 मीटर पर पक्का रोड़ एवं पश्चिम दिशा में 440 मीटर पर रोड़ है। इसी प्रकार दक्षिण दिशा में 55 मीटर पर कच्चा रोड़ है। लीज के अंदर 02 कुएँ एवं 06 पेड़ (02 नीम एवं 04 बबूल) लगे हुए हैं। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि खदान क्षेत्र में 06 पेड़ हैं जिन्हें नहीं काटा जावेगा तथा वहाँ पर साईट आफिस इत्यादि का निर्माण किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक ने यह भी बताया कि ये सभी पेड़ क्षेत्र में विद्यमान दोनों कुओं के आसपास हैं चूँकि उत्पादन क्षमता 4763 मी³/वर्ष है इसलिए इस क्षेत्र में खनन नहीं किया जायेगा। प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक से निम्नानुसार जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए :-

- ✓ परियोजना प्रस्तावक का शपथ पत्र कि लीज क्षेत्र में विद्यमान पेड़ों को नहीं काटा जायेगा तथा कुएँ के आसपास के क्षेत्र को नॉन माईनिंग जोन घोषित किया जावेगा।
- ✓ समिति द्वारा सुझाये अनुसार पुनरीक्षित सी.ई.आर. योजना।

567वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 29 अप्रैल 2022

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतीकरण के दौरान चाही गई जानकारी दिनांक 29/04/22 द्वारा दी गई, जिसे समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया जो संतोषजनक पाई गई। परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक-ए अनुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता स्टोन— 4,763 मी³ प्रति वर्ष।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 09.92 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 02.00 प्रति वर्ष।
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 01.00 लाख :-

सी.ई.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि		राशि (रु. में)
1	स्कूल में 100 वृक्ष ट्री गार्ड एवं नाम प्लेट के साथ प्रजाति - नीम,मौलश्री,कचनार,कदम, पुत्रन्जीवा I	50,000
2	श्यामपुर चितौनी गाँव के आंगनवाड़ी केंद्र में 1 वर्ष तक पोषण आहार वितरण	50,000
कुल		1,00,000

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 2400 वृक्षों का वृक्षारोपण :

वृक्षारोपण हेतु नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा संख्या
बैरियर जोन	नीम, करंज, पीपल, चिरोल, सीताफल एवं अन्य प्रजातियाँ।	1800
परिवहन मार्ग (पौधों की न्यूनतम ऊँचाई एक मीटर)	नीम, करंज, चिरोल, जंगल जलेबी ट्री-गार्ड के साथ	60
विद्यालय में	मौलश्री, पुत्रन्जीवा, कचनार, कदम, नीम	100
नॉन माइनिंग जोन	नीम, करंज, चिरोल, सीताफल एवं अन्य स्थानीय प्रजाति	440
कुल		2400

11. जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, जिला छिंदवाड़ा (म.प्र.) ।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (सिया) ने पत्र क्रमांक 185 दिनांक 20/04/22 के माध्यम से शिवपुरी जिले की 02 जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (1. जिला खनिज (रेत) सर्वेक्षण प्रतिवेदन जिला छिंदवाड़ा (म.प्र.) - वर्ष 2021-22 एवं 2. जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (खनिज रेत को छोड़कर) जिला छिंदवाड़ा (म.प्र.) - वर्ष 2021-22) राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति के परीक्षण हेतु भेजी गई है जो राज्य स्तरीय मूल्यांकन समिति को दिनांक 22/4/22 को प्राप्त हुई।

567वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 29 अप्रैल 2022

उक्त जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति के सदस्यों को दिनांक 26/04/22 को प्रेषित की गई थी तथा उस पर चर्चा राज्य स्तरीय मूल्यांकन समिति की 567वीं बैठक दिनांक 29/04/22 में प्रस्तावित की गई ।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की 567वीं बैठक दिनांक 29/04/22 में शिवपुरी जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट पर चर्चा की गई जिसमें पाया गया कि :—

- ✓ कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छिंदवाड़ा द्वारा प्रस्तुत जिला खनिज (रेत) सर्वेक्षण प्रतिवेदन जिला छिंदवाड़ा (म.प्र.) – वर्ष 2021–22 एवं 2. जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (खनिज रेत को छोड़कर) जिला छिंदवाड़ा (म.प्र.) – वर्ष 2021–22 के अनुसार दोनों जिला सर्वेक्षण रिपोर्टों का अनुमोदन गठित समिति द्वारा किया गया है जिसका गठन सभी जिलों हेतु संचालक, प्रशासन एवं खनिकर्म, भोपाल ने पत्र क्रमांक 2981 दिनांक 03/03/22 के माध्यम से किया है एवं तत्संबंध में आदेश कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छिंदवाड़ा के पत्र क्रमांक 392 दिनांक 22/03/22 के द्वारा किया गया है ।
- ✓ इसी प्रकार कार्यालय (खनिज शाखा) जिला छिंदवाड़ा म.प्र. ने पत्र क्रमांक—553/खनि. शाखा/2022, दिनांक 18/04/22 के माध्यम से अवगत कराया है कि इस जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट पर सुझाव आमंत्रित करने बावत् उसे जिले के पोर्टल पर 21 दिवस के लिए अपलोड करने बावत् पत्र क्रमांक 441 दिनांक 25/3/22 के माध्यम से जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी को लिखा गया है ।
- ✓ राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकारी (सिया) के पत्र क्रमांक 185 दिनांक 20/04/22 के माध्यम से छिंदवाड़ा जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 25/07/18 के अनुसार अधिकांश जानकारीयों समाहित की गई है किंतु जानकारीयों पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 25/07/18 के अनुसार निर्धारित फार्मेट के क्रमानुसार नहीं है। समिति ने पाया कि इन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में एमओईएफ नोटिफिकेशन, 25/07/2018 के अनुसार छिंदवाड़ा जिले में हरित क्षेत्र के विकास हेतु प्रस्तावित पौधों की प्रजातियों की जानकारी भी दी गई है जो खनिज पट्टों के ब्योरों की तालिका में उल्लेखित है जिसके साथ निर्धारित लक्ष्य के विरुद्ध कितना वृक्षारोपण किस वर्ष किया है, उसको भी आगे से अंकित किया जाना चाहिए ।
- ✓ इन जिला सर्वेक्षण रिपोर्टों पर सुझाव आमंत्रित करने बावत् उसे जिला पोर्टल अपलोड करने हेतु कार्यालय (खनिज शाखा) जिला छिंदवाड़ा म.प्र. के पत्र क्रमांक 441 दिनांक 25/3/22 के माध्यम से जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी को लिखा गया है ।
- ✓ कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छिंदवाड़ा म.प्र. ने पत्र दिनांक 27/4/22 के माध्यम से पुनरीक्षित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल को प्रस्तुत की है, जिसकी प्रतिलिपि राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति को भी

567वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 29 अप्रैल 2022

दी है, जिसमें उल्लेख किया है कि जिला छिंदवाड़ा की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट को नियमानुसार 21 दिवस हेतु आमजन के सुझाव बावत् एन.आई.सी. छिंदवाड़ा के पोर्टल पर दिनांक 28/3/22 को अपलोड किया गया था जिसकी 21 दिन की अवधि दिनांक 17/4/22 को समाप्त हुई तथा इस अवधि में 02 सुझाव प्राप्त हुए जिनमें पर्यावरणीय अनुमतियों अनुसार वृक्षारोपण की जानकारी एवं फोटोग्राफ नहीं दिये जाने एवं उत्खनन के कारण होने वाली बीमारियों की जानकारी नहीं दी गई है। इसी प्रकार पूर्व में प्रस्तुत रेत खनिज की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में रेत पुर्नभरण की जानकारी में टंकण त्रुटि हुई थी जिनको सुधारा गया है।

चर्चा उपरांत समिति की यह अनुशंसा है कि चूंकि छिंदवाड़ा जिले की दोनों जिला सर्वेक्षण रिपोर्टें (खनिज-रेत एवं रेत को छोड़कर अन्य गौण खनिज) पर आमजन के सुझाव आमंत्रित कर इनका अनुमोदन जिले में गठित समिति द्वारा किया जा चुका है अतः समिति द्वारा सुझाई गई उपरोक्त अनुशंसाओं के साथ छिंदवाड़ा जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट का अनुमोदन किया जाना प्रस्तावित है। प्रकरण आगामी कार्यवाही राज्य स्तरीय पर्यावरण समझौते निर्धारण प्राधिकारण की ओर अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

12.जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, जिला छतरपुर (म.प्र.) ।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समझौते निर्धारण प्राधिकारण (सिया) ने पत्र क्रमांक 226 दिनांक 26/04/22 के माध्यम से छतरपुर जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति के परीक्षण हेतु भेजी गई है। उक्त जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति के सदस्यों को दिनांक 27/04/22 को प्रेषित की गई थी तथा उस पर चर्चा राज्य स्तरीय मूल्यांकन समिति की 567वीं बैठक दिनांक 29/04/22 में प्रस्तावित की गई।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की 567वीं बैठक दिनांक 29/04/22 में छतरपुर जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट पर चर्चा की गई जिसमें पाया गया कि :—

- ✓ इसी प्रकार कार्यालय (खनिज शाखा) जिला छतरपुर म.प्र. ने पत्र क्रमांक—1037/खनि/2022, दिनांक 25/4/22 के माध्यम से अवगत कराया है कि इस जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट पर सुझाव आमंत्रित करने बावत् उसे जिले के पोर्टल पर दिनांक 12/3/22 को अपलोड किया गया था तथा 30 दिन के भीतर 03 आवेदन प्राप्त हुए थे जिनका नियमानुसार निराकरण कराया गया।
- ✓ कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छतरपुर म.प्र. के पत्र क्रमांक—1037/खनि/2022, दिनांक 25/4/22 में उल्लेखित किया गया है कि उपरोक्तानुसार प्राप्त सुझावों के निराकरण उपरांत समिति द्वारा इस जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट का अनुमोदन किया गया है।
- ✓ राज्य स्तरीय पर्यावरण समझौते निर्धारण प्राधिकारण (सिया) ने पत्र क्रमांक 226 दिनांक

567वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 29 अप्रैल 2022

26/04/22 के माध्यम से छतरपुर जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 25/07/18 के अनुसार अधिकांश जानकारीयों समाहित की गई है परंतु बिंदु क्रमांक-30 (एमओईएफ नोटिफिकेशन, 25/07/2018 के अनुसार बिंदु क्रमांक 26) की जानकारी जो माईनर मिनरल (रेत छोड़कर) से संबंधित है, में छतरपुर जिले में हरित क्षेत्र के विकास हेतु प्रस्तावित पौधों की प्रजातियों की जानकारी दी गई है किंतु पूर्व के वर्षों में लीज धारकों द्वारा किये गये वृक्षारोपण की जानकारी नहीं दी गई है। जिला खनिज अधिकारी, छतरपुर ने अपने ई-मेल दिनांक 29/4/22 (जो सिया द्वारा भी 29/4/22 को सेक को फारवर्ड किया गया) के माध्यम से पूर्व के वर्षों में लीज धारकों द्वारा किये गये वृक्षारोपण की जानकारी की तालिका एवं फोटोग्राफ प्रस्तुत किये हैं। इस पुनरीक्षित वृक्षारोपण की तालिका के अवलोकन से ज्ञात होता है कि कुछ संचालित खदानों में वृक्षारोपण की जानकारी दी गई है तथा कुछ में नहीं दी गई है जिसको अद्यतन किया जाना चाहिए। साथ ही निर्धारित लक्ष्य के विरुद्ध कितना वृक्षारोपण किस वर्ष किया है, उसको भी अंकित किया जाना चाहिए। अतः समिति का सुझाव है कि इस जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट को अद्यतन किया जाये उसमें बिंदु क्रमांक-30 की जानकारी (एमओईएफ नोटिफिकेशन, 25/07/2018 के अनुसार बिंदु क्रमांक 26) सभी संचालित खदानों बावत् समाहित की जाये।

चर्चा उपरांत समिति की यह अनुशंसा है कि छतरपुर जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट पर आमजन के सुझाव आमंत्रित कर इनका अनुमोदन जिले में गठित समिति द्वारा किया जा चुका है। अतः समिति द्वारा सुझाई गई उपरोक्त अनुशंसाओं के साथ छतरपुर जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट का अनुमोदन किया जाना प्रस्तावित है। प्रकरण आगामी कार्यवाही राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण की ओर अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

13. जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, जिला बालाघाट (म.प्र.) ।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (सिया) ने पत्र क्रमांक 224 दिनांक 24/04/22 के माध्यम से बालाघाट जिले की जिला सर्वेक्षण राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति के परीक्षण हेतु भेजी गई है। उक्त जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति के सदस्यों को दिनांक 27/04/22 को प्रेषित की गई थी तथा उस पर चर्चा राज्य स्तरीय मूल्यांकन समिति की 567वीं बैठक दिनांक 29/04/22 में प्रस्तावित की गई।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की 562वीं बैठक दिनांक 29/03/22 में शिवपुरी जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट पर चर्चा की गई जिसमें पाया गया कि :-

- ✓ कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बालाघाट म.प्र. ने पत्र क्रमांक-620/खनिज/2022, दिनांक 25/4/22 के माध्यम से अवगत कराया है कि इस जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट रिपोर्ट 2021-22 का गठित समिति द्वारा अनुमोदन उनकी बैठक दिनांक 20/04/22 में किया गया है। जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट हेतु गठित समिति के कार्यवाही दिनांक 20/4/22 में

567वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 29 अप्रैल 2022

उल्लेखित है कि "गठित समिति के उपस्थित समस्त सदस्यगण/अधिकारीगण के समक्ष जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में तैयार प्रारूप 2021-22 की खनिज रेत एवं अन्य खनिजों के जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (डी.एस.आर.) का अवलोकन / परीक्षण किया गया । पूर्व बैठक दिनांक 25/3/22 को डी.एस.आर. में उल्लेखित सभी बिंदुओं पर चर्चा की गई । सस्टेनेबल सेंड माईनिंग मैनेजमेंट गाइडलाईन 2016 एवं इनफोर्समेंट माईनिंग फॉर सेंड माईनिंग, 2020 गाइड लाईन अनुसार पाये जाने के फलस्वरूप जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (डी.एस.आर.) के प्रारूपों को भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 15/1/18 तथा अधिसूचना दिनांक 25/7/18 के परिशिष्ट-10 अनुसार कार्यवाही हेतु खनिज अधिकारी के माध्यम से स्थानीय स्तर पर दावा, आपत्ति / अनापत्ति हेतु जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी, कलेक्ट्रेट बालाघाट के कार्यालयीन पत्र क्रमांक 483 दिनांक 25/3/22 एवं जिला सूचना एवं प्रकाशन अधिकारी बालाघाट को कार्यालयीन पत्र क्रमांक 487 दिनांक 25/3/22 द्वारा स्थानीय स्तर पर इशतहार प्रकाशन दिनांक से 21 दिवस के अंदर, दावा, आपत्ति/अनापत्ति प्रस्तुत किये जाने हेतु लेख किया गया था जिसके तहत उक्त के संबंध में आज दिनांक तक तैयार की गई जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के दावा, अपत्ति/अनापत्ति प्राप्त होना नहीं पाया गया है । जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट खनिज रेत एवं अन्य खनिजों की तैयार किये जाने के उपरांत स्थानीय स्तर पर किसी भी प्रकार दावा, अपत्ति/अनापत्ति प्राप्त नहीं होने से तैयार की गई । जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट प्रारूप को सर्वसम्मति से गठित समिति द्वारा अनुमोदन किया गया"।

- ✓ जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट हेतु गठित समिति के कार्यवाही दिनांक 20/4/22 में यह भी उल्लेखित है प्रकाशन अधिकारी बालाघाट को कार्यालयीन पत्र क्रमांक 487 दिनांक 25/3/22 द्वारा स्थानीय स्तर पर इशतहार प्रकाशन दिनांक से 21 दिवस के अंदर, दावा, आपत्ति/अनापत्ति प्रस्तुत किये जाने हेतु लेख किया गया था जिसके तहत उक्त के संबंध में आज दिनांक तक तैयार की गई जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के दावा, अपत्ति/अनापत्ति प्राप्त होना नहीं पाया गया है ।
- ✓ राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकारी (सिया) के पत्र क्रमांक 3581 दिनांक 25/03/22 के माध्यम से बालाघाट जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 25/07/18 के अनुसार अधिकांश जानकारियाँ समाहित की गई है परंतु बिंदु क्रमांक-30 (एमओईएफ नोटिफिकेशन, 25/07/2018 के अनुसार बिंदु क्रमांक 26) की जानकारी में बालाघाट जिले में हरित क्षेत्र के विकास हेतु प्रस्तावित पौधों की प्रजातियों की जानकारी दी गई है किंतु पूर्व के वर्षों में लीज धारकों द्वारा किये गये वृक्षारोपण की जानकारी नहीं दी गई है । अतः समिति का सुझाव है कि इस जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट को अपडेट किया जाये एवं बिंदु क्रमांक-30 की जानकारी (एमओईएफ नोटिफिकेशन, 25/07/2018 के अनुसार बिंदु क्रमांक 26) उसमें समाहित की जाये ।

चर्चा उपरांत समिति की यह अनुशंसा है कि चूंकि बालाघाट जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट का

567वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 29 अप्रैल 2022

अनुमोदन जिले में गठित समिति द्वारा दिनांक 20/4/22 की बैठक में किया जा चुका है अतः समिति द्वारा सुझाई गई उपरोक्त अनुशांसाओं के साथ बालाघाट जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट का अनुमोदन किया जाना प्रस्तावित है। प्रकरण आगामी कार्यवाही राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण की ओर अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है ।

14. जिला सर्वेक्षण रिपोर्टों के संबंध में राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति के सुझाव -

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 25/07/18 के अनुसार सभी गौण खनिजों हेतु जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट तैयार की जानी है । इस अधिसूचना के अनुसार प्रदेश के जिलों से जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट सिया के माध्यम से सेक परीक्षण हेतु भेजी जा रही है । इन जिला सर्वेक्षण रिपोर्टों पर समिति की आज दिनांक 29/04/22 को आयोजित बैठक में समिति के सदस्यों का सुझाव है कि जब भी इन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट को अद्यतन किया जाये तब वृक्षारोपण की जानकारी में पर्यावरणीय अभिस्वीकृति प्राप्त उत्खनन पट्टों में लक्ष्य के विरुद्ध किये गये वृक्षारोपणों की संख्या भी दर्ज की जाये । इसी प्रकार राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति का मत है कि राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से अनुरोध करें कि की अधिसूचना दिनांक 25/07/18 के परिशिष्ट-10 “बालू खनन या नदी तल खनन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट तैयार करने के लिए प्रक्रिया” के निर्धारित फार्मेट में “जिले में पहले से ही अनुदत्ता पट्टों के संबंध में पौधारोपण और हरित पट्टी विकास” की जानकारी भी सम्मिलित की जाये ।

(ए.ए. मिश्रा)
सदस्य सचिव

(डॉ. पी.सी. दुबे)
अध्यक्ष

567वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 29 अप्रैल 2022

Following standard conditions shall be applicable for the mining projects of minor mineral in addition to the specific conditions and cases appraised for grant of TOR:

Annexure- 'A'

Standard conditions applicable to Stone/Murram and Soil quarries:

1. Mining should be carried out as per the submitted land use plan and approved mine plan. The regulations of danger zone (500 meters) prescribed by Directorate General of Mines safety shall also be complied compulsorily and necessary measures should be taken to minimize the impact on environment.
2. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars and fenced from all around the site. Necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
3. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded.
4. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
5. Mineral evacuation road shall be made pucca (WBM/black top) by PP.
6. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.
7. Crusher with inbuilt APCD & water sprinkling system shall be installed minimum 100 meters away from the road and 500 meters away from the habitations only after the permissions of MP Pollution Control Board with atleast 04 meters high wind breaking wall of suitable material to avoid fugitive emissions.
8. Working height of the loading machines shall be compatible with bench configuration.
9. Slurry Mixed Explosive (SME) shall be used instead of solid cartridge.
10. The OB shall be reutilized for maintenance of road. PP shall bound to compliance the final closure plan as approved by the IBM.
11. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.
12. Six monthly occupational health surveys of workers shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights.
13. A separate bank account should be maintained for all the expenses made in the EMP and CER activities by PP for financial accountability and these details should be provided in Annual Environmental Statement. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
14. To avoid vibration, no overcharging shall be carried out during blasting and muffle blasting shall be adopted. Blasting shall be carried out through certified blaster only and no explosive will be stored at mine site without permission from the competent authority.
15. Mine water should not be discharged from the lease and be used for sprinkling & plantations. For surface runoff and storm water garland drains and settling tanks (SS pattern) of suitable sizes shall be provided.
16. All garland drains shall be connected to settling tanks through settling pits and settled water shall be used for dust suppression, green belt development and beneficiation plant. Regular de-silting of drains and pits should be carried out.
17. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
18. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.
19. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area. PP shall take Socio-economic activities in the region through the 'Gram Panchayat'.
20. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.

567वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 29 अप्रैल 2022

21. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product - mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.
22. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
23. All the mines where production is > 50,000 cum/year, PP shall develop its own website to display various mining related activities proposed in EMP & CER along with budgetary allocations. All the six monthly progress report shall also be uploads on this website along with MoEF&CC & SEIAA, MP with relevant photographs of various activities such as garland drains, settling tanks, plantation, water sprinkling arrangements, transportation & haul road etc. PP or Mine Manager shall be made responsible for its maintenance & regular updation.
24. All the soil queries, the maximum permitted depth shall not exceed 02 meters below general ground level & other provisions laid down in MoEF&CC OM No. L-11011/47/2011-IA.II(M) dated 24/06/2013.
25. The mining lease holders shall after ceasing mining operation, undertake re-grassing the mining area and any other area which may have been disturbed due to their mining activities and restore the land to a condition which is fit for growth of fodder, flora , fauna etc. Moreover, a separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020.
26. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEF&CCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".
27. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
28. Authorization (if required) under Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016 should be obtained by the PP if required.
29. A display board with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
 - a. Lease owner's Name, Contact details etc.
 - b. Mining Lease area of the project (in ha.)
 - c. Production capacity of the project.
30. Dense plantation/ wood lot shall be carryout in the 7.5 meters periphery/barrier zone of the lease through concern CCF (social forestry) or concerned DFO or any other suitable agency and on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
31. Entire plantation proposed in barrier zone of lease area shall be carried out in the first year itself as per submitted plantation scheme and along the fencing seed sowing of Neem, Babool, Safed Castor etc shall also be carried out.
32. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
33. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.
34. During initial three years before onset of monsoon season, minimum 100 saplings or maximum as per submitted plantation scheme and subsequently approved by the SEAC of fodder / native fruit bearing species shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/ Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh "ANKUR YOJNA" by registering individual villagers on "Vayudoot app". Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Aganwadi premises.
35. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.

567वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 29 अप्रैल 2022

36. Activates proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.

37. खदान क्षेत्र में किये जाने वाले वृक्षारोपण हेतु निर्देश।

नोट 1 :- स्थल विशेष हेतु प्रजातियों के चयन में स्थानीय मृदा के प्रकार, संरचना, गहराई को ध्यान में रखकर रोपण किया जाना चाहिए।

नोट 2 :- विषय विशेषज्ञ, उक्त विषय में रुचि रखने वाले स्थानीय जानकारों से राय ली जाने की सलाह है।

नोट 3 :- पौधों की बढ़त हेतु सड़ी गोबर की खाद, केचुआ खाद, आवश्यक होने पर अच्छी मृदा का उपयोग, समय पर रोपण, पौधों की देख-रेख, मृदा नमी को बनाये रखने हेतु जल-संरचनाओं का निर्माण, निदाई-गुड़ाई, सिंचाई एवं सुरक्षा का पर्याप्त उपाय करना चाहिए।

नोट 4 :- पौधों की ऊँचाई/गोलाई -

नोट 5 :- भू-क्षरण स्थल पाये जाने पर भू-संरक्षण का कार्य किया जाना चाहिए।

नोट 6 :- रोपित पौधों का मापदंड एवं अन्य कार्य

क्र.	स्थल	ऊँचाई न्यूनतम	गोलाई न्यूनतम
1.	बैरियर जोन/नॉन माईनिंग क्षेत्र	02.5 फिट	03 से. मी.
2.	रोड साईड/स्कूल/ ऑगनवाडी	03.5 फिट	05 से.मी.
3.	पौधों के चारों ओर निदाई-गुड़ाई, थाला (1.5 मी.गोलाई में) बनाना तीन वर्षों तक।		
4.	आवश्यकतानुसार सिंचाई।		

नोट 7 :- बीज बुआई एवं अंकुरण पश्चात् देख-रेख -

- स्थानीय स्तर पर बीज संग्रहण एवं गुड़ाई/जुताई पश्चात् वर्ष पूर्ण बीज रोपण। जामुन, महुआ, नीम, साल बीज का रोपण बीज गिरने के तुरंत (07 दिवस के अंदर) पश्चात् ही रोपण।
- बीज रोपण पश्चात् अंकुरण एवं 4 से 6 पत्तियाँ आने पर, पौधे के चारों तरफ निदाई-गुड़ाई एवं सड़ी गोबर की खाद डालना।
- बीज रोपण तीन वर्षों तक लगातार पौधों की जीवितता एवं सफलता के आधार पर करना।
- सीड-बाल विधि से भी बीज रोपण किया जा सकता है।

Annexure- 'B'

Standard conditions applicable for the Sand Mine Quarries*

1. District Authority should annually record the deposition of sand in the lease area (at an interval of 100 meters for leases 10 ha or > 10.00 ha and at an interval of 50 meters for leases < 10 ha.) before monsoon & in the last week of September and maintain the records in RL (Reduce Level) Measurement Book. Accordingly authority shall allow lease holder to excavate only the replenished quantity of sand in the subsequent year.
2. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars. Necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
3. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded.
4. Only registered vehicles/tractor trolleys with GPS which are having the necessary registration and permission for the aforesaid purpose under the Motor Vehicle Act and also insurance coverage for the same shall alone be used for said purpose.
5. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
6. Mineral evacuation road shall be made Pucca (WBM/black top) by PP.
7. Sand and gravel shall not be extracted up to a distance of 1 kilometer (1Km) from major bridges and highways on both sides, or five times (5x) of the span (x) of a bridge/public civil structure (including water intake points) on up-stream

567वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 29 अप्रैल 2022

side and ten times (10x) the span of such bridge on down-stream side, subjected to a minimum of 250 meters on the upstream side and 500 meters on the downstream side.

8. Mining depth should be restricted to 3 meters or water level, whichever is less and distance from the bank should be 1/4th or river width and should not be less than 7.5 meters. No in-stream mining is allowed. Established water conveyance channels should not be relocated, straightened, or modified.
9. Demarcation of mining area with pillars and geo-referencing should be done prior to the start of mining.
10. PP shall carry out independent environmental audit atleast once in a year by reputed third party entity and report of such audit be placed on public domain.
11. No Mining shall be carried out during Monsoon season.
12. The mining shall be carried out strictly as per the approved mine plan and in accordance with the Sustainable Sand Mining Management Guidelines, 2016 and Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining, 2020 issued by the MoEF&CC ensuring that the annual replenishment of sand in the mining lease area is sufficient to sustain the mining operations at levels prescribed in the mining plan.
13. If the stream is dry, the excavation must not proceed beyond the lowest undisturbed elevation of the stream bottom, which is a function of local hydraulics, hydrology, and geomorphology.
14. After mining is complete, the edge of the pit should be graded to a 2.5:1 slope in the direction of the flow.
15. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.
16. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.
17. Six monthly occupational health surveys of workers shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights. All these facilities such as rest shelters, site office etc. Shall be removed from site after the expiry of the lease period.
18. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020 and these details should be provided in Annual Environmental Statement.
19. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
20. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
21. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.
22. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area.
23. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.
24. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product - mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.
25. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
26. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M dated 16/01/2020.
27. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEFCCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".
28. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
29. A display board with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
 - a. Lease owner's Name, Contact details etc.

567वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 29 अप्रैल 2022

- b. Mining Lease area of the project (in ha.)
- c. Production capacity of the project.
30. Following conditions must be implemented by PP in case of sand mining as per NGT (CZ) order dated 19/10/2020 in OA NO. 66/2020 and SEIAA's instruction vide letter No. 5084 dated 09/12/2020.
 - i. The Licensee must use minimum number of poclains and it should not be more than two in the project site.
 - ii. The District Administration should assess the site for Environmental impact at the end of first year to permit the continuation of the operation.
 - iii. The ultimate working depth shall be 01 m from the present natural river bed level and the thickness of the sand available shall be more than 03 m the proposed quarry site.
 - iv. The sand quarrying shall not be carried out blow the ground water table under any circumstances. In case, the ground water table occurs within the permitted depth at 01 meter, quarrying operation shall be stopped immediately.
 - v. The sand mining should not disturb in any way the turbidity, velocity and flow pattern of the river water.
 - vi. The mining activity shall be monitored by the Taluk level Force once in a month by conducting physical verification.
 - vii. After closure of the mining, the licensee shall immediately remove all the sheds put up in the quarry and all the equipments used for operation of sand quarry. The roads/pathways shall be leveled to let the river resume its normal course without any artificial obstruction to the extent possible.
 - viii. The mined out pits to be backfilled where warranted and area should be suitable landscaped to prevent environmental degradation.
 - ix. PP shall adhere to the norms regarding extent and depth of quarry as per approved mining plan. The boundary of the quarry shall be properly demarcated by PP.
31. Species such as Khus Slips and Nagar Motha shall be planted on the river banks for bank stabilization and to check soil erosion while on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
32. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
33. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.
34. During initial three years before onset of monsoon season, minimum 100 saplings or maximum as per submitted plantation scheme and subsequently approved by the SEAC of fodder / native fruit bearing species shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/ Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh "ANKUR YOJNA" by registering individual villagers on "Vayudoot app". Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Aganwadi premises.
35. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
36. Activates proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.
38. खदान क्षेत्र में किये जाने वाले वृक्षारोपण हेतु निर्देश।

नोट 1 :- स्थल विशेष हेतु प्रजातियों के चयन में स्थानीय मृदा के प्रकार, संरचना, गहराई को ध्यान में रखकर रोपण किया जाना चाहिए।

नोट 2 :- विषय विशेषज्ञ, उक्त विषय में रुचि रखने वाले स्थानीय जानकारों से राय ली जाने की सलाह है।

567वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 29 अप्रैल 2022

नोट 3 :- पौधों की बढ़त हेतु सड़ी गोबर की खाद, केचुआ खाद, आवश्यक होने पर अच्छी मृदा का उपयोग, समय पर रोपण, पौधों की देख-रेख, मृदा नमी को बनाये रखने हेतु जल-संरचनाओं का निर्माण, निदाई-गुड़ाई, सिंचाई एवं सुरक्षा का पर्याप्त उपाय करना चाहिए ।

नोट 4 :- पौधों की ऊँचाई/गोलाई –

नोट 5 :- भू-क्षरण स्थल पाये जाने पर भू-संरक्षण का कार्य किया जाना चाहिए ।

नोट 6 :- रोपित पौधों का मापदंड एवं अन्य कार्य

क्र.	स्थल	ऊँचाई न्यूनतम्	गोलाई न्यूनतम्
1.	बैरियर जोन/नॉन माईनिंग क्षेत्र	02.5 फिट	03 से. मी.
2.	रोड़ साईड/स्कूल/ ऑगनवाडी	03.5 फिट	05 से.मी.
3.	पौधों के चारों ओर निदाई-गुड़ाई, थाला (1.5 मी.गोलाई में) बनाना तीन वर्षों तक ।		
4.	आवश्यकतानुसार सिंचाई ।		

नोट 7 :- बीज बुआई एवं अंकुरण पश्चात् देख-रेख –

- स्थानीय स्तर पर बीज संग्रहण एवं गुड़ाई/जुताई पश्चात् वर्ष पूर्ण बीज रोपण। जामुन, महुआ, नीम, साल बीज का रोपण बीज गिरने के तुरंत (07 दिवस के अंदर) पश्चात् ही रोपण ।
- बीज रोपण पश्चात् अंकुरण एवं 4 से 6 पत्तियाँ आने पर, पौधे के चारों तरफ निदाई-गुड़ाई एवं सड़ी गोबर की खाद डालना।
- बीज रोपण तीन वर्षों तक लगातार पौधों की जीवितता एवं सफलता के आधार पर करना ।
- सीड-बाल विधि से भी बीज रोपण किया जा सकता है।

Annexure- 'C'

Standard conditions applicable for the Sand deposits on Agricultural Land/ Khodu Bharu Type Sand Mine Quarries*

1. Mining should be done only to the extent of reclaiming the agricultural land.
2. Only deposited sand is to be removed and no mining/digging below the ground level is allowed.
3. The mining shall be carried out strictly as per the approved mining plan.
4. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars and necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
5. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded.
6. The mining activity shall be done as per approved mine plan and as per the land use plan submitted by PP.
7. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
8. Mineral evacuation road shall be made Pucca (WBM/black top) by PP.
9. For carrying out mining in proximity to any bridge and/or embankment, appropriate safety zone on upstream as well as on downstream from the periphery of the mining site shall be ensured taking into account the structural parameters, location aspects, flow rate, etc., and no mining shall be carried out in the safety zone.
10. No Mining shall be carried out during Monsoon season.
11. The mining shall be carried out strictly as per the approved mine plan and in accordance with the Sustainable Sand Mining Management Guidelines, 2016 issued by the MoEF&CC.
12. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.
13. Thick plantation shall be carryout on the banks of the river adjacent to the lease, mineral evacuation road and common area in the village. PP would maintain the plants for five years including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations.

567वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 29 अप्रैल 2022

14. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.
15. Six monthly occupational health surveys of workers shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights.
16. A separate bank account should be maintained for all the expenses made in the EMP and CER activities by PP for financial accountability and these details should be provided in Annual Environmental Statement. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
17. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
18. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.
19. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area.
20. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.
21. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product - mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.
22. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
23. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020.
24. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEFCCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".
25. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
26. A display board with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
 - a. Lease owner's Name, Contact details etc.
 - b. Mining Lease area of the project (in ha.)
 - c. Production capacity of the project.
27. Species such as Khus Slips and Nagar Motha shall be planted on the nearby river banks for bank stabilization and to check soil erosion while dense plantation/ wood lot shall be carryout in the 7.5 meters periphery/barrier zone of the lease through concern CCF (social forestry) and on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
28. Dense plantation/ wood lot shall be carryout in the 7.5 meters periphery/barrier zone of the lease through concern CCF (social forestry) or concerned DFO or any other suitable agency and on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
29. Entire plantation proposed in barrier zone of lease area shall be carried out in the first year itself as per submitted plantation scheme.
30. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and

567वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 29 अप्रैल 2022

fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.

31. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. Plantation in adjoining forest land shall be carried out through concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
32. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.
33. During initial three years before onset of monsoon season, minimum 100 saplings or maximum as per submitted plantation scheme and subsequently approved by the SEAC of fodder / native fruit bearing species shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/ Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh "ANKUR YOJNA" by registering individual villagers on "Vayudoot app". Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Aganwadi premises.
34. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
35. Activates proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.
36. खदान क्षेत्र में किये जाने वाले वृक्षारोपण हेतु निर्देश।

नोट 1 :- स्थल विशेष हेतु प्रजातियों के चयन में स्थानीय मृदा के प्रकार, संरचना, गहराई को ध्यान में रखकर रोपण किया जाना चाहिए।

नोट 2 :- विषय विशेषज्ञ, उक्त विषय में रुचि रखने वाले स्थानीय जानकारों से राय ली जाने की सलाह है।

नोट 3 :- पौधों की बढ़त हेतु सड़ी गोबर की खाद, केचुआ खाद, आवश्यक होने पर अच्छी मृदा का उपयोग, समय पर रोपण, पौधों की देख-रेख, मृदा नमी को बनाये रखने हेतु जल-संरचनाओं का निर्माण, निदाई-गुड़ाई, सिंचाई एवं सुरक्षा का पर्याप्त उपाय करना चाहिए।

नोट 4 :- पौधों की ऊँचाई/गोलाई -

नोट 5 :- भू-क्षरण स्थल पाये जाने पर भू-संरक्षण का कार्य किया जाना चाहिए।

नोट 6 :- रोपित पौधों का मापदंड एवं अन्य कार्य

क्र.	स्थल	ऊँचाई न्यूनतम	गोलाई न्यूनतम
1.	बैरियर जोन/नॉन माईनिंग क्षेत्र	02.5 फिट	03 से. मी.
2.	रोड़ साईड/स्कूल/ ऑगनवाडी	03.5 फिट	05 से.मी.
3.	पौधों के चारों ओर निदाई-गुड़ाई, थाला (1.5 मी.गोलाई में) बनाना तीन वर्षों तक।		
4.	आवश्यकतानुसार सिंचाई।		

नोट 7 :- बीज बुआई एवं अंकुरण पश्चात् देख-रेख -

- स्थानीय स्तर पर बीज संग्रहण एवं गुड़ाई/जुताई पश्चात् वर्ष पूर्ण बीज रोपण। जामुन, महुआ, नीम, साल बीज का रोपण बीज गिरने के तुरंत (07 दिवस के अंदर) पश्चात् ही रोपण।
- बीज रोपण पश्चात् अंकुरण एवं 4 से 6 पत्तियों आने पर, पौधे के चारों तरफ निदाई-गुड़ाई एवं सड़ी गोबर की खाद डालना।
- बीज रोपण तीन वर्षों तक लगातार पौधों की जीवितता एवं सफलता के आधार पर करना।
- सीड-बाल विधि से भी बीज रोपण किया जा सकता है।

Annexure- 'D'

General conditions applicable for the granting of TOR

1. The date and duration of carrying out the baseline data collection and monitoring shall be informed to the concerned Regional Officer of the M.P Pollution Control Board.

567वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 29 अप्रैल 2022

2. During monitoring, photographs shall be taken as a proof of the activity with latitude & longitude, date, time & place and same shall be attached with the EIA report. A drone video showing various sensitivities of the lease and nearby area shall also be shown during EIA presentation.
3. An inventory of various features such as sensitive area, fragile areas, mining / industrial areas, habitation, water-bodies, major roads, etc. shall be prepared and furnished with EIA.
4. An inventory of flora & fauna based on actual ground survey shall be presented.
5. Risk factors with their management plan should be discussed in the EIA report.
6. The EIA report should be prepared by the accredited consultant having no conflict of interest with any committee processing the case.
7. The EIA document shall be printed on both sides, as far as possible.
8. All documents should be properly indexed, page numbered.
9. Period/date of data collection should be clearly indicated.
10. The letter /application for EC should quote the SEIAA case No./year and also attach a copy of the letter prescribing the TOR.
11. The copy of the letter received from the SEAC prescribing TOR for the project should be attached as an annexure to the final EIA/EMP report.
12. The final EIA/EMP report submitted to the SEIAA must incorporate all issues mentioned in TOR and that raised in Public Hearing with the generic structure as detailed out in the EIA report.
13. Grant of TOR does not mean grant of EC.
14. The status of accreditation of the EIA consultant with NABET/QCI shall be specifically mentioned. The consultant shall certify that his accreditation is for the sector for which this EIA is prepared. If consultant has engaged other laboratory for carrying out the task of monitoring and analysis of pollutants, a representative from laboratory shall also be present to answer the site specific queries.
15. On the front page of EIA/EMP reports, the name of the consultant/consultancy firm along with their complete details including their accreditation, if any shall be indicated. The consultant while submitting the EIA/EMP report shall give an undertaking to the effect that the prescribed TORs (TOR proposed by the project proponent and additional TOR given by the MOEF & CC) have been complied with and the data submitted is factually correct.
16. While submitting the EIA/EMP reports, the name of the experts associated with involved in the preparation of these reports and the laboratories through which the samples have been got analyzed should be stated in the report. It shall be indicated whether these laboratories are approved under the Environment (Protection) Act, 1986 and also have NABL accreditation.
17. All the necessary NOC's duly verified by the competent authority should be annexed.
18. PP has to submit the copy of earlier Consent condition /EC compliance report, whatever applicable along with EIA report.
19. The EIA report should clearly mention activity wise EMP and CER cost details and should depict clear breakup of the capital and recurring costs along with the timeline for incurring the capital cost. The basis of allocation of EMP and CER cost should be detailed in the EIA report to enable the comparison of compliance with the commitment by the monitoring agencies.
20. A time bound action plan should be provided in the EIA report for fulfillment of the EMP commitments mentioned in the EIA report.
21. The name and number of posts to be engaged by the PP for implementation and monitoring of environmental parameters should be specified in the EIA report.
22. EIA report should be strictly as per the TOR, comply with the generic structure as detailed out in the EIA notification, 2006, baseline data is accurate and concerns raised during the public hearing are adequately addressed.
23. The EIA report should be prepared by the accredited consultant having no conflict of interest with any committee processing the case.
24. Public Hearing has to be carried out as per the provisions of the EIA Notification, 2006. The issues raised in public hearing shall be properly addressed in the EMP and suitable budgetary allocations shall be made in the EMP and CER based on their nature.
25. Actual measurement of top soil shall be carried out in the lease area at minimum 05 locations and additionally N, P, K and Heavy Metals shall be analyzed in all soil samples. Additionally in one soil sample, pesticides shall also be analyzed.
26. A separate budget in EMP & CER shall be maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020.

567वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 29 अप्रैल 2022

27. PP shall submit biological diversity report stating that there is no adverse impact in- situ and on surrounding area by this project on local flora and fauna's habitat, breeding ground, corridor/ route etc. This report shall be filed annually with six-monthly compliance report.
28. The project proponent shall provide the mitigation measures as per MoEFCCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area" with EIA report.
29. LPG gas shall be provided for camping labour under "Ujjwala Yojna .
30. In the project where ground water is proposed as water source, the project proponent shall apply to the competent authority such as Central Ground Water Authority (CGWA) as the case may be for obtaining, No Objection Certificate (NOC).
31. Consideration of mining proposals involving violation of the EIA Notification, 2006, the project proponent shall give an undertaking by way of affidavit to comply with all the statutory requirements and judgment of Hon'ble Supreme Court of India dated 02/08/2017 in WP © No. 114 of 2014 in the matter of Common Cause V/s Union of India & others before grant of TOR/EC. The under taking interalia includes commitment of the PP not to repeat any such violation in future as per MoEF&CC OM No. F.NO. 3-50/2017-IA.III (Pt.) dated 30/05/2018.
32. The mining project proponents involving violations of the EIA Notification, 2006 under the provisions of S.O. 804 (E) dated 14/03/2017 and subsequent amendments for TOR/EC shall give an undertaking by way of affidavit to comply with all the statutory requirements and judgment of Hon'ble Supreme Court dated the 2nd August 2017 in Writ Petition (Civil) No. 114 of 2014 in the matter of Common Cause versus Union of India and Ors. Before grant of TOR/EC the undertaking inter-alia include commitment of the PP not to repeat any such violation of future. In case of violation of above undertaking, the TOR/Environmental Clearance shall be liable to be terminated forthwith.
33. Under CER scheme commitments with physical targets shall be included in EIA report for:
 - ✓ Proposal for CER activities based upon commitment made during public hearing and COVID-19 pandemic.
 - ✓ Activities such as solar panels in school, awareness camps for Oral Hygiene, Diabetes and Blood Pressure, works related to plantation (distribution of fruit & fodder bearing trees) vaccination, cattle's health checkup etc. in concerned village shall be proposed.
 - ✓ No fuel wood shall be used as a source of energy by mine workers. Thus proposal for providing solar cookers / LPG gas cylinders under "Ujjwala Yojna" to them who are residing in the nearby villages, shall be considered.
 - ✓ PP's commitment that activities proposed in the CER scheme will be completed within initial 03 years of the project and in the remaining years shall be maintained shall be submitted with EIA report.
34. Under Plantation Scheme commitments with budgetary allocations shall be included in EIA report for :
 - ✓ Comprehensive green belt plan with commitment that entire plantation shall be carried out in the initial three years and will be maintained thereafter with causality replacement. Proposal for distribution of fruit bearing species for nearby villagers shall also be incorporated in the plantation scheme and for which a primary survey for need assessment in concerned village shall be carried out.
 - ✓ Commitment that plantation shall be carried out preferably through Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
 - ✓ Commitment that high density plantation (preferably using "Miyawaki Technique or WALMI technique) shall be developed in 7.5m barrier zone left for plantation through concern CCF (social forestry) or concerned DFO or any other suitable agency.
 - ✓ Commitment that local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land suitable for the purpose through Gram Panchayat on suitable community land in the concerned village area and handed over to Gram Panchayat after lease period.
 - ✓ PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
 - ✓ Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, minimum 50 saplings be planted considering 80% survival.

567वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 29 अप्रैल 2022

- ✓ Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
35. खदान क्षेत्र में किये जाने वाले वृक्षारोपण हेतु निर्देश।

- नोट 1 :-** स्थल विशेष हेतु प्रजातियों के चयन में स्थानीय मृदा के प्रकार, संरचना, गहराई को ध्यान में रखकर रोपण किया जाना चाहिए।
- नोट 2 :-** विषय विशेषज्ञ, उक्त विषय में रुचि रखने वाले स्थानीय जानकारों से राय ली जाने की सलाह है।
- नोट 3 :-** पौधों की बढ़त हेतु सड़ी गोबर की खाद, केचुआ खाद, आवश्यक होने पर अच्छी मृदा का उपयोग, समय पर रोपण, पौधों की देख-रेख, मृदा नमी को बनाये रखने हेतु जल-संरचनाओं का निर्माण, निदाई-गुड़ाई, सिंचाई एवं सुरक्षा का पर्याप्त उपाय करना चाहिए।
- नोट 4 :-** पौधों की ऊँचाई/गोलाई –
- नोट 5 :-** भू-क्षरण स्थल पाये जाने पर भू-संरक्षण का कार्य किया जाना चाहिए।
- नोट 6 :-** रोपित पौधों का मापदंड एवं अन्य कार्य

क्र.	स्थल	ऊँचाई न्यूनतम	गोलाई न्यूनतम
1.	बैरियर जोन/नॉन माईनिंग क्षेत्र	02.5 फिट	03 से. मी.
2.	रोड साईड/स्कूल/ ऑगनवाडी	03.5 फिट	05 से.मी.
3.	पौधों के चारों ओर निदाई-गुड़ाई, थाला (1.5 मी.गोलाई में) बनाना तीन वर्षों तक।		
4.	आवश्यकतानुसार सिंचाई।		

- नोट 7 :-** बीज बुआई एवं अंकुरण पश्चात् देख-रेख –

- स्थानीय स्तर पर बीज संग्रहण एवं गुड़ाई/जुताई पश्चात् वर्ष पूर्ण बीज रोपण। जामुन, महुआ, नीम, साल बीज का रोपण बीज गिरने के तुरंत (07 दिवस के अंदर) पश्चात् ही रोपण।
- बीज रोपण पश्चात् अंकुरण एवं 4 से 6 पत्तियाँ आने पर, पौधे के चारों तरफ निदाई-गुड़ाई एवं सड़ी गोबर की खाद डालना।
- बीज रोपण तीन वर्षों तक लगातार पौधों की जीवितता एवं सफलता के आधार पर करना।
- सीड-बाल विधि से भी बीज रोपण किया जा सकता है।

FOR PROJECTS LOCATED IN SCHEDULED (V) TRIBAL AREA , following should be studied and discussed in EIA Report before Public Hearing as per the instruction of SEIAA vide letter No. 1241 dated 30/07/2018.

36. Detailed analysis by a National Institute of repute of all aspects of the health of the residents of the Schedule Tribal block.
37. Detailed analysis of availability and quality of the drinking water resources available in the block.
38. A study by CPCB of the methodology of disposal of industrial waste from the existing industries in the block, whether it is being done in a manner that mitigate all health and environmental risks.
39. The consent of Gram Sabah of the villages in the area where project is proposed shall be obtained.